



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2017/फाल्गुन 2, 1938

No. 61]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2017/PHALGUNA 2, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 6 फरवरी, 2017

सं.टी.एएमपी/68/2016-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, पारादीप पत्तन पर, आयातित कोयला के प्रहस्तन के लिए बीओटी आधार पर नई कोयला बर्थ के विकास के लिए पारादीप पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का इसके साथ संलग्न आदेश अनुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टी.एएमपी/68/2016-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास

.....

आवेदक

कोरम

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन (सदस्य वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य(आर्थिक)

आदेश

(जनवरी 2017 के दूसरे दिन पारित)

इस प्राधिकरण द्वारा महापत्तनों पर परियोजनाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु 2008 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पारादीप पत्तन न्यास(पीपीटी) पर डीप ड्रॉट कोयला बर्थ पर तापीय कोयला तथा तापीय कोयला से अन्य कार्गो के प्रहस्तन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के लिए 14 जुलाई 2008 के आदेश सं. टी.एएमपी/18/2008-पीपीटी पारित किया गया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में 16 अगस्त 2008 को राजपत्र सं. 133 पर अधिसूचित किया गया था।

1.2. तत्पश्चात पीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टी.एएमपी/44/2015-पीपीटी दिनांक 04 सितंबर 2015, बीओटी आधार पर पीपीटी पर बर्थ—सीक्यू। और 2 के मशीनीकरण के लिए संदर्भ प्रशुल्क निर्धारण हेतु जारी किया था। इस कार्य के लिए पीपीटी द्वारा तब प्रशुल्क दिशानिर्देश-2013 का संदर्भ लेते हुए जुलाई 2008 में डीप ड्रॉट कोयला बर्थ के लिए निर्धारित प्रशुल्क को निर्धारित किया गया था। यह आदेश 29 सितंबर 2015 को भारत के राजपत्र सं. 335 पर अधिसूचित किया गया था। डोलोमाईट और

चूना पत्थर के लिए कोयला की दर का अनुकरण 04 सितंबर 2015 के कथित आदेश के आधार पर कि डोलोमाईट और चूना पत्थर के संबंध में प्रहस्तन दरें और कार्य निष्पादन मानक वही होंगे जो उपयोग क्षमता के 10 प्रति के बारे में कोयला और डोलोमाईट और चूना पत्थर घटकों का 10 प्रतिशत हैं किया गया है।

2.1. इस परिप्रेक्ष्य में पीपीटी ने दिनांक 03 नवंबर 2016 के पत्र सं. सीई/डीसी/लेखा/4/16(भाग-1)/1075 के द्वारा बीओटी आधार पर पीपीटी पर बर्थ-सीक्यू 1 और 2 के विकास हेतु बीओटी आधार पर मशीनीकरण के लिए संदर्भ प्रशुल्क निर्धारण हेतु कोयले के लिए निर्धारित संदर्भ प्रशुल्क का अनुकरण करते हुए रु. 655.56 करोड़ की लागत से 10 मिलियन टन प्रति वर्ष की इष्टतम क्षमता सहित आयातित कोयले के प्रहस्तन के लिए नई कोयला बर्थ के विकास के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। पीपीटी ने अपने प्रस्ताव में यह उल्लेख किया है कि अपरिहार्य कारणों से बीओटी आधार पर डीप ड्राफ्ट कोयला बर्थ विकास के लिए हस्ताक्षरित रियायत करार को समाप्त किया जाना अपेक्षित था तथा परियोजना के लिए लागत अनुमानों को अद्यतित करने के पश्चात पुनः निविदा की व्यवस्था की गई है :

2.2. पीपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क इस प्रकार है:

(क). कार्गो प्रहस्तन प्रभार :

क्रम सं.	वस्तु	इकाई	दर रु. प्रति मी. टन	
			विदेशगामी	तटीय
(क)	कोयला प्रहस्तन प्रभार (तापीय कोयला)	प्रति मीट्रिक टन	175.60	175.60
(ख)	कोयला प्रहस्तन प्रभार (तापीय कोयला से भिन्न कार्गो)	प्रति मीट्रिक टन	175.60	105.36

(ख). बर्थ किराया प्रभार:

दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसका भाग(रु. में)

क्रम सं.	पोत	विदेशगामी पोत	तटीय पोत
1	सभी पोत	1.00	0.59

(ग). भंडारण प्रभार :

क्रम सं.	विवरण	निशुल्क अवधि के पश्चात प्रथम 10 दिन के लिए दर	26वें दिन से आगे शेष कार्गो के लिए
1.	कोयला (सभी प्रकार का)	रु. 16.21 प्रति मी.टन	रु.32.42 प्रति मी टन

2.3. पीपीटी ने भी कार्य निष्पादन मानक का प्रस्ताव किया था.

3.1. पूर्वोक्तानुसार, पीपीटी के प्रस्ताव अनुरूप अपनाए जाने वाले सितंबर 2015 के प्रशुल्क आदेशमें कोयलाए चूना पत्थर और डोलोमाईट के संबंध में प्रशुल्क निर्धारित है। जबकि प्रस्तावित नई बर्थ में तापीय कोयला, तापीय कोयला से भिन्न अन्य कार्गो के प्रहस्तन के लिए संकल्पना की गई है। प्रदत्त है कि डीप ड्राफ्ट कोयला बर्थ के लिए कोयला, तापीय कोयला से भिन्न अन्य कार्गो के प्रहस्तन के लिए अप्रफ्रंट प्रशुल्क उपलब्ध हैं इसलिए उपयुक्त माना गया कि प्रस्तावित नई कोयला बर्थ के लिए संदर्भ प्रशुल्क हेतु उचित सूचकांकन के साथ कथित अप्रफ्रंट प्रशुल्क अपना लिया जाए।

3.2 इस संदर्भ में पीपीटी से अनुरोध किया गया था हमारे 22 नवंबर, 2016 के पत्र के माध्यम से कुछ जानकारी और स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया था। पीपीटी ने अपने 02 दिसंबर, 2016 के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी तथा उस पर पीपीटी का प्रतिक्रिया का सारांश नीचे तालिका बद्ध रूप में उल्लेखित है:-

क्रम संख्या	हमारे द्वारा दी गई सूचना/ सफाई	पीपीटी की प्रतिक्रिया
(i)	<p>पीपीटी के उपर्युक्त पत्र में देखा गया है कि पीपीटी ने आदेश सं. टीएएमपी/44/2015-पीपीटी दिनांक 04 सितंबर, 2015 के द्वारा बर्थ सं. सीक्यू- 1 व 2 के मशीनीकरण के लिए, नई प्रस्तावित बर्थ में तापीय कोयला तथा तापीय कोयला से भिन्न कार्गो अपनाने के लिए प्रस्ताव किया है।</p> <p>इस संबंध में, उल्लेख किया गया है कि उपर्युक्त संदर्भित सितंबर, 2015 में, कोयला, चूना पत्थर और डोलोमाइट के बारे में संदर्भ प्रशुल्क निर्धारित है जबकि प्रस्तावित नई बर्थ में तापीय कोयला और तापीय कोयला से भिन्न कार्गो के प्रहस्तन की संकलपना की गई है।</p> <p>पीपीटी को ज्ञात है कि डीप ड्रॉट कोल बर्थ पर तापीय कोयला और तापीय कोयला से भिन्न कार्गो के प्रहस्तन के लिए पीपीटी हेतु आदेश सं. टीएएमपी/18/2008 पीपीटी दिनांक जुलाई में अप्रकट प्रशुल्क पहले ही तय किया जा चुका है। इस प्रकार कथित अप्रकट प्रशुल्क अपनाने के लिए (उपयुक्त सूचकांकन सहित), प्रस्तावित नये डीप ड्रॉट कोयला बर्थ हेतु संदर्भ प्रशुल्क के प्रस्ताव करने का क्या कारण है।</p>	<p>स्मरण रहे कि 'बीओटी आधार पर पारादीय पतन पर सीक्यू- 1 और 2 की मशीनीकरण परियोजना के लिए संदर्भ प्रशुल्क 04 सितंबर, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/44/2015 -पीपीटी के तहत अधिसूचित किए गए थे जो टीएएमपी के आदेश सं. टीएएमपी/18/2008-पीपीटी दिनांक जुलाई 2008 के अंतर्गत आयोजित कोयला के लिए पूर्व, अनुमोदित सूचकांकन के पश्चात प्रशुल्क के आधार पर आधारित थे।</p> <p>इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा, पत्र सं. टीएएमपी वर्ष 2016-17/12/2009-विविध दिनांक 11 अप्रैल 2016 के द्वारा सूचकांकन घटक शून्य घोषित किया गया है। अतः वर्तमान प्रस्ताव के लिए परिकल्पित संदर्भ प्रशुल्क दोनों स्थितियों में जैसे (I) आदेश सं. टीएएमपी / 18/2008-पीपीटी दिनांक जुलाई, 2008 के द्वारा अधिसूचित परविचार करते हुए (या) (II) आदेश सं. टीएएमपी / 44 / 2015- पीपीटी दिनांक 04 सितंबर, 2015 के अंतर्गत कोयला घटक के लिए विचारित वर्ष 2016-17 के लिए सूचकांकन घटक शून्य पर विचार करते हुए परिकल्पित करने पर एक समान रहेगा।</p>
(ii)	<p>जब बीओटी आधार पर डीप ड्रॉट बर्थ के विकास का रियायत करार कर दिया गया है तो दिनांक 04 सितंबर, 2015 के आदेश में तापीय कोयला, तापीय कोयला से भिन्न, चूना प्रत्थर और डोलोमाइट) के लिए सी क्यू- 1 और 2 बर्थों के मशीनीकरण के लिए डीप ड्राफ्ट कोयला बर्थ पर तापीय कोयला और तापीय कोयला से भिन्न प्रशुल्क उपलब्ध होने की स्थिति में निर्धारित संदर्भ प्रशुल्क अपनाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। इस पूर्ण औचित्य बताएं।</p>	<p>उपर्युक्त उल्लेखानुसार वर्तमान परियोजना में दोनों परिदृश्यों में संदर्भ प्रशुल्क एक समान होगा। चूना पत्थर या डोलोमाइट का वर्तमान में प्रस्ताव के संदर्भ प्रशुल्क में कोई उल्लेख नहीं होगा।</p>
(iii)	<p>इसके अलावा, पीपीटी द्वारा अब प्रस्तुत दी गई जानकारी / परियोजना विवरण से देखा गया है कि परियोजना की पूंजी लागत का आकलन रुपये 655.56 करोड़ किया गया है। इस संबंध में 14 जुलाई, 2008 के आदेश संख्या टीएएमपी/ 18/2008 -पीपीटी दिनांक 14 जुलाई, 2008 या आदेश संख्या टीएएमपी/ 44/ 2015 के अप्रकट प्रशुल्क अपनाने में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या प्रत्याशी प्रचालक पीपीटी अपने द्वारा प्रस्तावित दरें अपनाने पर स्वयं संतुष्ट है :-</p> <p>(क) प्रचालन लागत तथा लागत पूंजी पर 16 प्रतिशत प्रत्यागम रुपये 655.56 करोड़ वसूल करने की स्थिति में होगा</p> <p>(ख) लागत पूंजी + निवेश पूंजी पर 16 प्रतिशत प्रत्यागम अधिक वसूल नहीं कर पाएगा जिससे उसे हानि होगी।</p>	<p>पारादीय पतन पर बीओटी आधार पर आयातित कोयले के प्रहस्तन के लिए नई कोयल बर्थ के विकास के लिए प्रस्तावित परियोजना के लिए आरएफपी महा पतनों पर परियोजनाओं के लिए जुलाई 31, 2013 से प्रभारी प्रशुल्क निर्धारण हेतु नये संशोधित दिशा-निर्देश, 2013 नये दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा। अतः प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रशुल्क प्रस्ताव संदर्भ प्रशुल्क और कार्य निष्पादन मानकों सहित प्रस्तुत किया गया था।</p> <p>तथापि प्राधिकरण की आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में संशोधित आकलित लागत तथा 16 प्रतिशत प्रत्यागम पर विचार करते हुए तैयार किया गया है तथा प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि देखा जा सकता है यह रुपये 184.05 प्रति टन बनाम संदर्भ प्रशुल्क रुपये 175.60 प्रति टन वर्तमान प्रस्ताव की दर से निकलता है।</p> <p>जैसा कि नये दिशा-निर्देशों में पतन न्यासों को, उसी पतन न्यास के अंतर्गत एक वस्तुतः विशेष के लिए वही संदर्भ प्रशुल्क अपनाने की अनुमति दी गई है इसलिए पीपीटी ने आदेश संख्या टीएएमपी / 44/ 2015- पीपीटी दिनांक 04 सितंबर, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित, बीओटी आधार पर सी-क्यू-1 तथा 2 के</p>

		मशीनीकरण के लिए परियोजना के बारे में अधिसूचित प्रशुल्क (कोयला के लिए) अपनाने का प्रस्ताव किया है तथा वर्तमान स्तर तक प्राधिकरण के सूचकांकन मानको के अनुसार (2016 के लिए शून्य सूचकांकन घटक लेते हुए) यह एक समान निकलता है) सूचकांकित किया है।
(iv)	इसके अलावा यह भी पाया गया है कि प्रस्तावित दरमानों में पीपीटी द्वारा प्रस्तावित भंडारण स्लैब 2008 के अप्रेंट आदेश में निर्धारित स्लैब या सितंबर, 2015 के आदेश के साथ मेल नहीं खाते हैं।	<p>पूर्ववर्ती प्रशुल्क परिपत्र में भंडारण निशुल्क अवधि 10 दिन की तथा 10 दिन की निशुल्क अवधि के पश्चात भुगतान के लिए अलग-अलग स्लैब दिए गए थे। इस दौरान विभिन्न पतनों में स्थापित टर्मिनलों ने अनुभव किया कि इन प्रावधानों से अनेक गंभीर प्रचालकीय मुद्दे और विवाद उठे, पोत परिवहन मंत्रालय / भारतीय पतन संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आयातित कार्गो के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 30 दिन से अधिक पड़ाव भंडारण समय लगने की बात की है (प्रति संलग्न)</p> <p>कार्गो प्रहस्तन प्रभार और बर्थ किराया प्रभार के पूर्वानुमोदनानुसार प्रभार जैसी मुख्य विशेषताएं यथावत रखते हुए प्रशुल्क संबंधी वर्तमान प्रस्ताव में निशुल्क अवधि को 10 दिन से बढ़ाकर 15 दिन तथा निशुल्क अवधि से अधिक भंडारण दरों का स्लैब बढ़ाने संबंधी आशोधन किया गया है।</p>

3.3 देखने में आया है कि पीपीटी द्वारा किए गए प्रत्युत्तर से पीपीटी से कुछ जानकारीयां अपेक्षित थीं। हमने 13 दिसंबर, 2016 के अपने पत्र द्वारा पीपीटी से अनुरोध किया कि प्रत्युत्तर पर अपेक्षित कुछ जानकारीयां / सपष्टीकरण दे। पीपीटी ने 13 दिसंबर, 2016 के पत्र के माध्यम से अपना प्रत्युत्तर भेज दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारी और पीपीटी के उत्तर निम्नानुसार तालिका बद्ध किए गए हैं-

क्रम संख्या	हमारे द्वारा दी गई सूचना/ सफाई	पीपीटी की प्रतिक्रिया
1	पतन से मांगे गए विशेष स्पष्टीकरण के उत्तर में कि वह इस बात की सुनिश्चितता से संतुष्ट है कि प्रत्याशी बीओटी प्रचालक अनुज्ञेय प्रचालन लागत और नियोजित पूंजी पर 16 प्रतिशत पीपीटी की प्रस्तावित दरों के अनुसार वसूल कर सकेगा, पीपीटी ने परिकलन प्रस्तुत करते हुए दिखाया है कि रुपये 504.96 करोड़ की पूंजी लागत और प्रचालन लागत तथा पूंजी लागत पर 16 प्रतिशत प्रत्यागम के अनुसार प्रहस्तन दर रुपये 184.05 प्रति टन निकलती है और प्रस्तावित सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क रुपये 175.60 प्रति टन की दर प्रस्तावित सुविधा के लिए पीपीटी द्वारा सुझायी गई है। इस परिप्रेक्ष्य में पीपीटी से अनुरोध है कि दरों से कम होने से क्या भावी बीओटी प्रचालक को हानि नहीं होगी, की जांच करें।	<p>पारादीप पतन न्यास (पीपीटी) इस बात से संतुष्ट है कि उन्हीं स्तरों पर कार्गो प्रहस्तन प्रभार, जो बीओटी आधार पर सी क्यू-1 और 2 बर्थ के मशीनीकरण के लिए को, वैसे ही कार्गो प्रहस्तन प्रबंधन के लिए अनुमोदित है के अनुसार रखने पर सहमत है जिसकी समयानुसार निविदा की जाएगी।</p> <p>पूर्ववर्ती अधिसूचित प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी / 44 / 2015 -पीपीटी दिनांक 04 सितंबर, 2015 (.बीओटी आधार पर पारादाप पर सीक्यू-1 और 2 बर्थों के मशीनीकरण के लिए) ही वह मूल प्रलेख है जिसके आधार पर वर्तमान प्रस्ताव तैयार किया है। तदनुसार रुपये 175.60 /- प्रतिटन की कार्गो प्रहस्तन प्रभार दर (2015 के की तुलना में वर्तमान आधार पर सूचकांकित) का प्रस्ताव किया गया है।</p>
2.	पीपीटी द्वारा में प्रस्तावित भंडारण स्लैब, 2008 के अप्रेंट प्रशुल्क आदेश या सितंबर, 2015 के आदेश में	भंडारण प्रसार के लिए स्लैब निम्नानुसार है जैसा कि पीपीटी के विचार से व उचित माने गए हैं:-

	निर्धारित भंडारण स्लैबों के अनुरूप नहीं है के संबंध में पीपीटी ने पोत परिवहन मंत्रालय भारतीय पतन संख्या की प्रति सलंगन की है जिसमें वर्तमान परिदृश्य में पड़ाव की अवधि 30 दिन से अधिक का उल्लेख है। जुलाई, 2008 के आदेश में अनुमोदित भंडारण स्लैब और निशुल्क दिनों, तथा पतन द्वारा प्रस्तावित अल्लिक तुलनात्मक विवरण नीचे दिया जाता है:				क्र.सं.	वस्तु	15 निशुल्क दिनों के बाद बचे हुए बेलेंसन कार्गो के लिए पहले 10 दिनों की दर	26 वें दिन के बाद की दर
			कोयला (सभी प्रकार)	प्रति दिन 16.21 रुपये प्रति टन	प्रति दिन 32.42 रुपये प्रति टन			
	क्र.सं.	विवरण	जुलाई 2008 के अनुसार अपफ्रंट ट्रेफिक आदेश	पीपीटी के अनुसार प्रस्तावित न्यू कोल बर्थ				
	1	निशुल्क दिन	10	15				
	2	भंडारण स्लैब	निशुल्क अवधि के पश्चात 1 से 5 दिन के पश्चात 6 से 10 दिन 11वें दिन से आगे 1 दिन	निशुल्क दिनों के बाद 1-10 दिन 26वें दिन से आगे				
	निशुल्क अवधि और भंडारण स्लैबों में बहुत बड़े बदलाव के परिप्रेक्ष्य में पीपीटी यह स्थापित करने के लिए अनुरोध है कि अब प्रस्तावित निशुल्क अवधि और भंडारण स्लैब का विस्तृत विवरण के आधार पर प्रचालक भंडारण गतिविधियों से रुपये 131 लाख की वार्षिक राजस्व मांग को पूरा कर सकेगा जैसा कि जुलाई, 2008 के आदेश में मान लिया गया है।				पुर्व उल्लेख किया जाता है कि पूर्वाधिसूचित आदेश परिपत्र में पड़ाव के लिए निशुल्क अवधि 10 दिन और भिन्न-भिन्न पड़ावों का उल्लेख किया गया था। इसी दौरान स्थापित टर्मिनलों में (विभिन्न पतनों) ऐसे प्रावधानों से गंभीर प्रचालकीय मुद्दे और विवाद उत्पन्न हो गए। पोत परिवहन मंत्रालय / भारतीय पतन संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में भी उल्लेख किया है कि आयातित कार्गो के संबंध में पड़ाव समय 30 दिन से अधिक होता है। यद्यपि यह 2008 और 2015 में अधिसूचित प्रशुल्क से पुष्ट नहीं होता है, तथापि, पीपीटी ने आईपीए/एमओएस के परिदृश्य में प्रस्ताव किया है।			
	मानकों में परिवर्तन करके आशा की जाती है कि राजस्व की किसी प्रकार से हानि नहीं होगी क्योंकि प्रहस्तन के समग्र रूप से अतिरिक्त कार्गो प्रहस्तित होने की आशा की जाती है।							
3.	सीमित आकार के पोत (50000 टन) तथा पैनामैक्स आकार के पात (35000 टन) और सीमिति व पैना मैक्स पोतों के 80:20 अनुपात के आधार जैसा पीपीटी पर डीप ड्रॉट कोयला बर्थ की इष्टतम क्षमता के परिकलन में विचार किया गया है, समस्त प्रहस्तन निष्पादन 47,000 टन / दिन निकलते हैं। इसके एवज में पीपीटी ने निष्पादन मानक अनुसूची में न्यूनतम 30000 टन / दिन के निष्पादन का प्रस्ताव किया है। पीपीटी से उपयुक्त और प्राप्त किया जा सकने वाले कार्य निष्पादन मानक जो पीपीटी परियोजना की ईष्टतम क्वे क्षमता में विचारित निष्पादन (प्रहस्तन) से न तो कम हों जिन पर प्रशुल्क अपनाए जाने का विचार किया जा रहा है।				यह एक टंकण संबंधी त्रुटि है तथा समस्त बर्थ निष्पादन 48000 टन प्रति दिन होगा। प्रस्तावित कार्य निष्पादन मानकों की एक प्रति परिशिष्ट 'ख' के तौर पर संलग्न है।			

4. मामले पर कार्रवाई के दौरान एकत्रित समस्त जानकारी के आधार पर निम्न स्थिति उजागर होती है:-

- (i). इस प्राधिकरण द्वारा महापत्तनों पर परियोजनाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु 2008 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पारादीप पत्तन न्यास(पीपीटी) पर ड्रॉट कोयला बर्थ पर तापीय कोयला तथा तापीय कोयला से अन्य

कार्गो के प्रहस्तन के लिए अप्रफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के लिए 14 जुलाई 2008 के आदेश सं. टीएएमपी/18/2008-पीपीटी पारित किया गया था।

- (ii). तत्पश्चात संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 के खंड 2.2 के अनुसरण में जिसमें साथ साथ उल्लेख किया गया है कि संदर्भ प्रशुल्क संबंधित महा पत्तन न्यास मे प्रशुल्क दिशानिर्देश-2008 के अंतर्गत उस वस्तु के लिए निर्धारित उच्चतम प्रशुल्क होगा, पीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर प्राधिकरण द्वारा पीपीटी द्वारा तत्काली प्रस्तावित सीक्यू -1 और 2 बर्थों के मशीनीकरण के लिए संदर्भ प्रशुल्क निर्धारण संबंधी आदेश सं. टीएएमपी/44/2015-पीपीटी दिनांक 04 सितंबर, 2015 जारी किया गया। इस प्रकार संदर्भित प्रशुल्क, जुलाई 2008 में डीप ड्रॉट कायेला बर्थ के लिए निर्धारित अप्रफ्रंट प्रशुल्क का अनुकरण था। 04 सितंबर, 2015 के कथित आदेश में इस आधार पर कि प्रहस्तन दरें और डोलोमाइट तथा चूना पत्थर के संबंध में कार्य निष्पादन मान कोयला तथा डोलोमाइट की भांति ही जेलोमाइट और चूना पत्थर होगा, कोयला प्रहस्तन की दर का अनुकरण चूना पत्थर और डोलोमाइट के लिए भी किया गया था इस प्रकार कोयला, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट के लिए समान दरों का निर्धारण किया गया था।
- (iii). संदर्भगत मामले में पीपीटी ने तापीय कोयला, तापीय कोयला से भिन्न वस्तुओं के लिए नयी कोयला बर्थ की संकल्पना की है। इस प्रयोजन के लिए पीपीटी ने आरंभ में सितंबर, 2015 बर्थ सं. सीक्यू- 1 और 2 के मशीनीकरण के लिए निर्धारित कोयला के लिए प्रशुल्क को अपनाने का प्रस्ताव किया था। पीपीटी द्वारा सितंबर, 2015 का आदेश परिपालित किया गया था जैसे कि पहले भी उल्लेख किया गया है, में कोयला, चूना पत्थर और डोलोमाइट के प्रहस्तन के लिए संदर्भ प्रशुल्क निर्धारित किया गया है। जबकि प्रस्तावित नई बर्थ में केवल तापीय कोयला तापीय कोयला से भिन्न वस्तुओं के प्रहस्तन की संकल्पना की गई है। पीपीटी के प्रहस्ताव अनुसार चूना पत्थर और डोलोमाइट के प्रहस्तन की संकल्पना नहीं की गई है। उल्लेखित है कि पीपीटी के लिए तापीय कोयला और तापीय कोयला से भिन्न वस्तु का डीप ड्राट कोयला बर्थ पर प्रहस्तन के लिए प्रशुल्क टीएएमपी/ 18 / 2008 दिनांक 14 जुलाई 2008 के द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है आदेश संख्या इस लिए यह प्राधिकरण पीपीटी को जुलाई 2008 के अप्रफ्रंट प्रशुल्क को (उपयुक्त सूचकांकन सहित अपनाने की अनुमति देती है। प्रस्तावित नई कोयला बर्थ के लिए प्रशुल्क न कि सितंबर, 2015 के आदेश में निर्धारित, कोयला के लिए दरें अपनाते हुए।
- (iv). वर्ष 2013 के संशोधित दिशानिर्देशों में उल्लेखित है कि 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रशुल्क निर्देश अपनाते समय थोक मूल्य सूचकांक में विचलन के 60 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाएगी जो परियोजना विशेष के लिए संदर्भ प्रशुल्क अधिसूचित करते समय दिशानिर्देशों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा जारी प्रशुल्क आदेश में निर्धारित अनुसार प्रासंगिक 01 जनवरी और आगामी वर्ष की 01 जनवरी के मध्य होगी।
पीपीटी पर डीप ड्रॉट कोयला बर्थ के लिए अप्रफ्रंट प्रशुल्क जुलाई, 2008 में अधिसूचित किया गया था। पीपीटी अप्रफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची में विशेष उल्लेख है कि प्रशुल्क दरों में थोक मूल्य सूचकांक का सूचकांकन के लिए आधार वर्ष, कथित आदेश में 01 जनवरी, 2008 अनुमोदित है। तदनुसार, पीपीटी ने प्रशुल्क सीमा-स्तर में, 35.08 प्रतिशत के सूचकांकन घटक के लिए अनुरोध किया है जो जुलाई 2008 के आदेश में पीपीटी पर डीप ड्रॉट कोयला बर्थ के लिए अनुमोदित है। यह सूचकांकन घटक वह सूचकांकन घटक है जो 01 जनवरी, 2008 के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2015 और 2016 के लिए सूचकांकन घटक शून्य बताया गया है।
इस प्रकार, पीपीटी द्वारा सूचकांकन घटक के आधार पर, प्रस्तावित सुविधा के लिए तापीय कोयला तथा तापीय कोयला से भिन्न वस्तुओं के प्रहस्तन के लिए सूचकांकित प्रशुल्क सही पाया गया है।
- (v). जुलाई, 2008 के प्रशुल्क आदेश में 10 दिन निशुल्क अवधि के तथा प्रभार्य स्लैब 1 से 5 दिन (निशुल्क अवधि के बाद) तथा 11 वें दिन से आगे के लिए अप्रफ्रंट प्रशुल्क आदेश निर्धारित है। नई कोयला बर्थ के लिए प्रस्तावित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची में 15 दिन निशुल्क अवधि तथा प्रभार्य अवधि निशुल्क अवधि के बाद 1 से 10 दिन तथा 26 वें दिन आगे के लिए स्लैब दिए गए हैं। निशुल्क अवधि तथा भंडारण संरचना में प्रस्तावित बदलाव के समर्थन में पीपीटी का कथन है कि विभिन्न पतनों में स्थापित टर्मिनलों पर निशुल्क अवधि तथा भंडारण स्लैबों के विषय पर प्रचालन की दृष्टि से गंभीर मुद्दों तथा विवादों का समाधान करना पड़ा है, इस संबंध में पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) / भारतीय पतन संस्था (आईपीए) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आयातित कार्गो के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पड़ाव का समय 30 दिन से अधिक होता है। इस स्थिति में आईपीए/एमओएस की रिपोर्ट के मद्देनजर, जुलाई, 2008 के अप्रफ्रंट प्रशुल्क आदेश की तुलना में पीपीटी ने निशुल्क दिनों में बढ़ोतरी और बढ़े हुए प्रभार्य भंडारण दिवस स्लैबों का प्रस्ताव किया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रस्तावित परिवर्तनों से भी पतन को कोई हानि होने का अंदेशा नहीं है। क्योंकि प्रहस्तन

की समस्त लागत के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त कार्गो आने की आशा की जा रही है। प्रदत्त है कि निशुल्क दिनों और भंडारण स्लैब में परिवर्तन आईपीए / एमओएस की रिपोर्ट के मद्देनजर किया गया है, जैसा कि पतन ने उल्लेख किया तथा पतन ने यह पुष्टि की है कि प्रस्तावित भंडारण स्लैब बदलावों के कारण पतन को कोई हानि नहीं होगी, इस संबंध में पतन का यह प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(vi). 2013 के संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश पतन न्यासों को उसी पतन में किसी विशेष वस्तु के लिए निर्धारित संदर्भ प्रशुल्क अपनाने के लिए अनुमति प्रदान करती है। पीपीटी स्वयं इसी प्रकार के कार्गो के लिए अनुमोदित प्रहस्तन प्रभार @ 175.60 /- प्रति टन को अपनाने के लिए तैयार है। इस संबंध में पतन का निर्णय विश्वस्तीय है।

(vii). प्रस्तावित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची में पीपीटी ने परिभाषाएं और सामान्य निबंधन एवं शर्तें जो पीपीटी की संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची का ही हिस्सा हैं का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि जुलाई, 2008 में अनुमोदित पीपीटी पर डीप ड्राट कोयला बर्थ के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची में परिभाषाएं व शर्तें और कार्गो प्रहस्तन प्रभार, भंडारण प्रभार और बर्थ किराया प्रभारों के अभिशासित करने वाले निबंधन एवं शर्तें निर्धारित नहीं की गई थीं जो सामान्यतया विभिन्न महापतन न्यासों की अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची में निर्धारित की जाती है।

तथापि, तत्पश्चात् पीपीटी पर सी-1 और 2 के मशीनीकरण के लिए संदर्भ प्रशुल्क अधिसूचित करते समय जो वर्ष 2008 में पीपीटी के लिए कोयला प्रहस्तन हेतु अपफ्रंट प्रशुल्क के लिए निर्धारित किया गया पर आधारित है, जो सामान्य निबंधन एवं शर्तें पीपीटी के आदेश सं. टीएएमपी / 44 / 2015 दिनांक 04 सितंबर 2014 के भाग के रूप में सभी प्रकार अभिशासित करने के लिए निर्धारित की गई थी। पीपीटी ने की वही परिभाषाएं सामान्य निबंधन एवं शर्तें तथा कार्गो प्रहस्तन तथा भंडार प्रभार से को अभिशासित करने वाली अन्य सभी शर्तें, जो संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची का ही भाग है, पीपीटी के संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची (आदेश सं. टीएएमपी / 44 / 2015 पीपीटी दिनांक 04 सितंबर, 2015) के समान है। पीपीटी द्वारा दरमानों में उल्लेखित परिभाषाएं और शर्तें अनुमोदित की जाती है।

इसके अतिरिक्त खंड - 3 में संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची के कार्गो प्रहस्तन प्रभार के प्रस्तावित नोट में पीपीटी ने एक वाक्य 'रेलवे वैगनों से कार्गो उतारे जाने के बाद के समय से' शामिल किया है। यह वाक्य 2008 या 2015 में अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची का भाग नहीं था। इसके अतिरिक्त यह वाक्य आयातित माल हेतु टर्मिनलों के लिए प्रासंगिक नहीं है परंतु जुलाई 2008 के आदेश के अनुसार निशुल्क अवधि जहाजी कार्य पूरा होने के बाद से आरंभ होगी। इसीलिए इस प्रावधान संबंधी नोट जोड़ दिया गया है। इस स्थिति में प्रस्तावित दरमानों से कथित वाक्य हटाया जाता है।

पोत संबंधी प्रभारों लगाने के लिए पोतों का वर्गीकरण, पोत संबंधी प्रभारों की पद्धति पोत संबंधी प्रभार तथा पोत संबंधी तटीय रियायती प्रभार, आदेश सं. टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी दिनांक 26 नवंबर, 2015 तथा 10 जून, 2016 के सभी के लिए साझे आदेश के संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची में दी गई शर्तों के अनुसार निर्धारण किया गया है।

(viii). बर्हिगमन प्राथमिकता बर्थिंग/प्राथमिक बर्थिंग मामलों में पीपीटी के दरमानों में निर्धारित प्रावधानों और जारी आदेशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। तदनुसार किसी पोत को बर्थिंग प्राथमिकता प्रदान करने से संबंधित एक नोट कि पीपीटी के वर्तमान दरमानों के अनुसार पतन एक दिन का बर्थ किराया प्रभार के समतुल्य या बर्थ में कुल पड़ाव के बर्थ किराया के 75 प्रतिशत के समतुल्य जो भी अधिक हो तथा बर्हिगमन प्राथमिकता बर्थिंग के लिए एक दिन के समतुल्य बर्थ किराया प्रभार या कुल पड़ाव के बर्थ किराया प्रभार का 100 प्रतिशत जो भी अधिक हो वसूल करेगा, भी संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची में निर्धारित किया गया है।

(ix). संदर्भ प्रशु दिशानिर्देशों 2013 के खंड 2.2 में अपेक्षा की गई है कि यह प्राधिकरण कार्य निष्पादन मानकों सहित एंडभ प्रशुल्क निर्धारित करें। यद्यपि 2013 के संशोधित दिशानिर्देशों में कार्य निष्पादन मानकों नियत करने की आवश्यकता नहीं है, यह मानते हुए कि पतन समुचित और प्राप्य कार्य निष्पादन मानक ही प्रस्तुत करेंगे।

कार्य निष्पादन मानकों के संबंध में पीपीटी ने समस्त कार्य निष्पादन 48000 टन /दिन का प्रस्ताव किया है। पीपीटी का कथन है कि समस्त कार्गो निष्पादन एक माह के अंदर पोत पर प्रहस्तित समस्त कार्गो को पोत के टर्मिनल में पड़ाव की अवधि से विभाजित करने के पश्चात् भागफल को कार्यदिवसों से गुणा करके निकाली जाएगी। पोतीय घंटों से कार्य दिवसों की संख्या निर्धारित करते समय कुल घंटों से 4 घंटे का समय बच अनुमत्त हेतु घटा(कम) कर दिए जाएंगे। 48000 घंटों का समस्त निष्पादन कैपसाइज पोतों (50000 टन) और पैनामैक्स पोतों (35000 टन) अनुपाततः क्रमशः 80:20 की औसत के आधार पर है तथा पीपीटी पर डीप ड्राट कोयल बर्थ के लिए। समस्त बर्थ के निष्पादन के संबंध में पीपीटी द्वारा प्रस्तावित कार्य निष्पादन मानक विश्वस्तीय माने जाते हैं।

- (x). जहां तक अंतरण भंडारण पड़ाव के लिए कार्य निष्पादन मानकों के निर्धारण का प्रश्न है पीपीटी का कथन है कि वैगनों पर लदान आरंभ होने से 15 दिन तक सभी प्रकार के कायेला पर होगा। पीपीटी ने प्राप्ति और प्रेषण के लिए 10 घंटों के एक प्रचालन कार्य का निर्धारण किया है ताकि दोहरे प्रचालन के लिए 18 घंटे का। पीपीटी द्वारा प्रस्तावित मानक यथावत निर्धारित किए जाते हैं
- (xi). कार्य निष्पादन अनुसूची के मानकों में, पीपीटी ने प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित शर्तों और लिक्विडिटी डेमेजेंस निर्धारित किए हैं। उल्लेख किया गया है कि निष्पादन का मूल्यांकन रिपोर्ट रियायतग्राही और / या रियायतग्राही और / के अभिलेखों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की तिमाही समीक्षा या रियायत प्रदाता प्राधिकरण द्वारा एक जांच के आधार पर किया जाएगा का गणना किया गया है द्वारा। रियायतग्राही हर औसत प्रदर्शन में 10% की कमी (दस प्रतिशत) के लिए संबंधित तिमाही के सकल राजस्व का 1% (एक प्रतिशत) की दर से निर्धारित किया लिक्विडिटी डेमेजेंस अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

कथित शर्त एक रियायत समझौते से संबंधित दलों के करार में उल्लेख के लिए प्रासंगिक है। निष्पादन मानक अनुसूची इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित रियायत प्रदाता प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही की रिपोर्ट की समीक्षा करने और लिक्विडिटी डेमेजेंस के भुगतान गवर्निंग शर्तों लिखने की जरूरत नहीं है। यदि पीपीटी चाहे तो ये पार्टियों के रियायत समझौते की शर्तों के रूप में हो सकती है और इसलिए इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित निष्पादन मानक अनुसूची में शामिल नहीं किया गया।

5.1. उपर्युक्त के अनुसार संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची इन्हें अभिशासित करने वाली शर्तों के आधार पर आशोधित कर दी गई है।

5.2. उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार पत्तन द्वारा यथाप्रस्तावित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची और कार्य निष्पादन मानक **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** पर संलग्न हैं।

5.3. परिणामतः उपर्युक्त कारणों और पूर्ण विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण पीपीटी पर नई कोयला बर्थ के लिए आशोधित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची अनुमोदित करता है तथा इसे कार्य निष्पादन मानकों सहित अधिसूचित करता है।

5.4. संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 के खंड 2.5 के अनुसार इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित संदर्भ प्रशुल्क तथा कार्य निष्पादन मानक, बोली दस्तावेज में उल्लिखित किए जाएंगे और पीपीपी परियोजनाओं के मामले में रियायत करार में उल्लिखित किए जाएंगे। तदनुसार, पीपीटी को, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क और कार्य निष्पादन मानकों को बोली दस्तावेज और बाद में पीपीपी परियोजनाओं के मामले में रियायत करार में शामिल करने की सलाह दी जाती है।

6.1. वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) के आरंभ होने की तारीख से उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक प्रशुल्क उस वर्ष के प्रासंगिक 'इंडेक्स' संदर्भ प्रशुल्क तक ही सीमित होगा। यह उपर्युक्त संदर्भ प्रशुल्क प्रशुल्क दिशानिर्देश-2013 के पैरा 2.2 में प्रदत्त इंडेक्सेशन के आधार पर स्वतः संशोधित किया जाएगा जो कि पूरी लाइसेंस अवधि के दौरान लागू रहेगा।

तथापि, लाइसेंसधारक, कार्य निष्पादन मानकों के साथ एक ऐसा प्रशुल्क ("कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क") प्रचालन के दूसरे वर्ष से आने वाले वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल से कम से कम 90 दिन पूर्व लगाने के लिए स्वतंत्र होगा जोकि उस प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए इंडेक्स संदर्भ प्रशुल्क से अलग होगा। ऐसा कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए इंडेक्स संदर्भ प्रशुल्क के 15% (और यह प्रशुल्क सीमा होगी) से अधिक नहीं होगा। कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से लागू हो जाएगा तथा पूरे वर्ष लागू रहेगा।

6.2. परियोजना के लाइसेंस करार के अधीन स्वतंत्र रूप से नियुक्त अभियंता के प्रमाण पत्र सहित इस प्राधिकरण को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें, पिछले 12 माह में या प्रचालन के पहले वर्ष के वास्तविक महीनों के दौरान जैसी भी स्थिति हो, लाइसेंस करार में शामिल कार्य निष्पादन संबंधी मानकों की उपलब्धियों का उल्लेख किया जाएगा।

6.3. प्रस्ताव प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर यह प्राधिकरण प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 के पैरा 5 में उल्लिखित कार्य निष्पादन मानकों की उपलब्धियों पर महापत्तन न्यास की राय आमंत्रित करेगा।

6.4. लाइसेंस धारक द्वारा पिछले 12 माह में रियायत करार में शामिल कार्य निष्पादन मानक हांसिल न किए जाने की स्थिति में यह प्राधिकरण आगामी वर्ष के लिए कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा तथा लाइसेंसधारक, आगामी वित्त वर्ष के लिए केवल इंडेक्स संदर्भ प्रशुल्क का पात्र होगा।

6.5. महापत्तन न्यास की राय पर विचार करने के पश्चात यदि यह प्राधिकरण पाता है कि लाइसेंस करार में शामिल कार्य निष्पादन मानकों का परिपालन किया गया है तो यह प्राधिकरण कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क आगामी वित्त वर्ष के लिए, 15 मार्च से पूर्व अधिसूचित कर देगा।

6.6. कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क पर विचार करते समय यह प्राधिकरण कार्य निष्पादनों तथा लाइसेंस धारक द्वारा इनके अनुपालन को जांचेगा। यह प्राधिकरण लाइसेंस धारक द्वारा कार्य निष्पादन मानकों के अनुपालन की उपलब्धियों या अन्यथा स्थिति के आधार पर कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क के प्रस्ताव को स्वीकार करने या रद्द करने के बारे में निर्णय लेगा। इंडेक्स्ड संदर्भ प्रशुल्क तथा कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क का निर्धारण प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 के साथ संलग्न परिशिष्ट के अनुसार किया जाएगा।

6.7. लाइसेंस धारक से प्रचालन के तीसरे वर्ष से प्राप्त कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क का प्रस्ताव पिछले 12 माह की कार्य निष्पादन उपलब्धियों के स्वतंत्र रूप से नियुक्त अभियंता के द्वारा सत्यापित होने पर इस प्राधिकरण द्वारा स्वतः ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। लाइसेंस धारक तीसरे वर्ष से कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क के लिए, स्वतंत्र अभियंता से उपलब्धियों के सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ मार्च की पहली तारीख से प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और यह प्राधिकरण 20 मार्च तक कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क आगामी वर्ष से लागू करने के लिए उसे अधिसूचित कर देगा।

6.8. जैसाकि संशोधित दिशानिर्देश, 2013 में निहित है कि किसी उपयोक्ता को इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कार्य निष्पादन संबंधी मानकों के लाइसेंस धारक के द्वारा पूरा करने के बारे में कोई शिकायत है तो वह इस प्राधिकरण को एक प्रतिवेदन दे सकता है। उसके पश्चात यह प्राधिकरण प्रतिवेदन के आधार पर एक जांच करेगा तथा अपनी निष्कर्ष रिपोर्ट पत्तन न्यास को दे देगा। पीपीटी निष्कर्ष रिपोर्ट पर लाइसेंस करार के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

6.9. लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने के 15 दिन के अंदर संबंधित प्रचालक लाइसेंस करार इस प्राधिकरण को भेजेगा जो इसे अपनी वेबसाइट पर लोड करेगा।

6.10. लाइसेंस धारक इस प्राधिकरण को कार्गो परिवहन शिप बर्थ की दिन की आऊटपुट तथा प्रत्येक बर्थ के लिए लगाए गए प्रशुल्क के बारे में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये तिमाही रिपोर्ट पीपीपी प्रचालक द्वारा प्रत्येक आगामी तिमाही की समाप्ति के बाद एक माह के अंदर प्रस्तुत की जाएंगी। इस प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अपेक्षित कोई अन्य सूचना भी इस प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

6.11 यह प्राधिकरण पीपीपी प्रचालक से प्राप्त सभी ऐसी सूचनाएं अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। तथापि, यह प्राधिकरण वह सूचना जो वाणिज्यिक दृष्टि से संवेदनशील हो, को वेबसाइट पर प्रकाशित न करने के लिए लाइसेंस धारक के अनुरोध पर विचार करेगा। ऐसे अनुरोध डाटा/सूचना के वाणिज्यिक दृष्टि से संवेदनशील होने के विस्तृत कारणों तथा उससे राजस्व/तथा प्रकाशन से प्रचालन पर होने वाले दुष्प्रभावों के साथ किए जाने चाहिए। इस संबंध में इस प्राधिकरण का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा।

टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./427/16(143)]

अनुलग्नक - 1

संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची

पारादीप पत्तन न्यास पर आयातित कोयला के प्रहस्तन के लिए बीओटी आधार पर नई कोयला बर्थ के विकास के लिए, संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची

1.1. परिभाषाएं – सामान्य

इन दरमानों में, जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

(i) "तटीय पोत" से तात्पर्य है कोई भी पोत जो केवल भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत में ही किसी अन्य पोत या स्थान के बीच कारोबार में लगा हुआ है और जिसके पास पोत परिवहन महानिदेशक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस है।

(ii) "विदेशगामी पोत" से तात्पर्य तटीय पोत से इतर कोई पोत है।

(iii) "दिन" से तात्पर्य किसी भी दिन के प्रातः 06.00 बजे से आरंभ होकर उसके आगामी दिन के प्रातः 06.00 बजे समाप्त होने वाली अवधि से है।

1.2. सामान्य निबंधन एवं शर्तें

(i) पोत संबंधी प्रभार लगाने के प्रयोजन से श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए "विदेशगामी" अथवा "तटीय" श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए पोत का दर्ज वर्गीकरण, "तटीय अथवा विदेशगामी" जैसा सीमा शुल्क विभाग अथवा पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी इसके प्रमाणन में दिया गया होगा, निर्णायक घटक होगा, और कार्गो की प्रकृति अथवा उसके उद्गम की इस प्रयोजन से कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।

(ii) (क) पोत संबंधी प्रभारों (वीआरसी) के लिए पोतों को वर्गीकृत करने की पद्धति :

- (i) सामान्य कारोबारी/व्यापारिक लाइसेंस धारी भारतीय ध्वज के किसी विदेशगामी पोत का, सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय धावक के रूप में परिवर्तन हो सकता है। प्रथम पत्तन पर सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय धावक के रूप में परिवर्तित किए जाने वाले पोत को भारतीय तट पर चलन के लिए, आगे सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ii) विदेशी पताका वाले विदेशगामी पोत का, पोत परिवहन महानिदेशक और सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश द्वारा विशिष्ट अवधि के लिए जारी तटीय यात्रा लाइसेंस के आधार पर तटीय धावक के रूप में परिवर्तन हो सकता है।

(ख) पोत संबंधी प्रभारों (वीआरसी) के लिए तटीय रियायती दर और विदेशी दर के मानदंड

- (i) परिवर्तन के ऐसे मामलों में लोड टर्मिनल (लदान टर्मिनल) द्वारा उस समय से तटीय दरें प्रभार्य होंगी जिस समय से पोत तटीय सामान लदान/चढ़ाना शुरू करता है।
- (ii) परिवर्तन के ऐसे मामलों में, तटीय दरें तभी तक प्रभार्य होंगी जब तक पोत भारतीय पत्तन पर आखिरी तटीय कार्गो को उतारने का प्रचालन पूरा करता है। उसके तुरंत बाद उत्तरायी वाले टर्मिनल द्वारा विदेशगामी दरें प्रभार्य हो जाएंगी।
- (iii) पोत परिवहन महानिदेशक से तटीय लाइसेंस प्राप्त एकनिष्ठ भारतीय तटीय पोतों से, तटीय दरों का पात्र होने के लिए कोई अन्य दस्तावेज अपेक्षित नहीं होगा।

(iii) कार्गो संबंधी प्रभारों (सीआरसी) के लिए तटीय रियायती दरों के मानदंड

- (क) वैश्विक और तटीय प्रचालन के लिए जारी सामान्य कारोबारी व्यापारिक लाइसेंस धारी भारतीय ध्वज के विदेशगामी भारतीय पोत के लिए, पोत से तट और क्वे से/को, भंडारणयार्ड से/को के लिए घाट भाड़ा सहित प्रहस्तन कार्य हेतु तटीय दरें, निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में लागू की जाएंगी:
 - (i) तटीय धावक में परिवर्तित और किसी भारतीय पत्तन से किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए तटीय कार्गो ले जाने वाला पोत।
 - (ii) तटीय धावक में परिवर्तित नहीं परंतु किसी भारतीय पत्तन से किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए तटीय कार्गो ले जाने वाला पोत।

*केंद्रीय सीमाशुल्क और सीमा कर बोर्ड के परिपत्र सं. 15/2002-कस्टम दिनांक 25 फरवरी 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज वाले विदेशगामी पोत द्वारा, बिना किसी सीमा शुल्क परिवर्तन के एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन तटीय कार्गो का वहन अनुमत्त है।

- (ख) तटीय धावक के रूप में परिवर्तित विदेशी ध्वज वाले पोत के मामलों में, पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा जारी विशिष्ट अवधि के लिए लाइसेंस और सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर, तैयार किसी भारतीय पत्तन से किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए संचालन हेतु तटीय कार्गो/ भारित कंटेनर पर कार्गो/कंटेनर के लिए तटीय दरें लागू होंगी।
- (iv) (क) सभी तटीय पोतों के लिए बर्थ किराया प्रभार अन्य पोतों के लिए समतुल्य प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
- (ख) तापीय कोयला और तापीय कोयला से भिन्न वस्तुओं के सभी तटीय कार्गो संबंधी प्रभार, सामान्य कार्गो कंटेनर संबंधी प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।
- (ग) कार्गो संबंधी प्रभारों के मामले में पोत तट स्थानान्तरण और क्वे से/को भंडारण यार्ड को/से प्रभारों हेतु (वार्फेज सहित सभी संबंधित प्रहस्तांतरण कार्यों के लिए) रियायती दरें प्रभार्य होंगी।
- (घ) विदेशी पत्तन का एक कार्गो से पत्तन 'ख' पर अनुवर्ती पोतारण हेतु पत्तन 'क' पर पहुंचने पर, उसके लिए तटीय चलन से प्रासंगिक रियायती प्रभार लागू होंगे। अन्य शब्दों में, उन पोतों को भारतीय पत्तन से कार्गो ले जाने/लाने के लिए तटीय चलन की अनुमति होगी और वे रियायत के पात्र होंगे।
- (v) विलंबित अदायगियों/वापसियों पर ब्याज:

- (क) उपयोक्ता, इन दरमानों के तहत विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा। उसी प्रकार टर्मिनल प्रचालक विलंबित वापसियों पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा।
- (ख) दंडात्मक ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक के प्राइम लेंडिंग दर से 2 प्रतिशत अधिक होगी।
- (ग) धन वापसी में देरी सेवाओं के पूरा होने के या उपभोगकर्ताओं से सभी जरूरी दस्तावेजों को लेने के 20 दिन बाद, जो कोई भी बाद में हो, संगणित किया जायेगा।
- (घ) उपभोक्ता द्वारा भुगतान में विलंब की गिनती, टर्मिनल प्रचालक द्वारा बिल के पेश करने की तिथि से 10 दिन बाद से आरंभ हो जाएगी लेकिन यह प्रावधान उन स्थितियों में लागू नहीं होगा जिनमें महापत्तन न्यास अधिनियम के अनुसार प्रभार का भुगतान सेवाएं लेने से पहले करने का उल्लेख किया गया है और/ या दन दरमानों में प्रभारों का अग्रिम भुगतान निर्धारित है।
- (vi) समग्र/कुल भार के परिमाण या किसी एक मद के परिमाण के लिए 0.5 तक का भिन्नातमक अंश 0.5 इकाई(यूनिट) माना जाएगा और 0.5 इकाई(यूनिट) या और उससे अधिक अंश को पूरा एक इकाई(यूनिट) माना जाएगा, बशर्ते अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।
- (vii) हिसाब किये गये सभी किराये/भाड़े को प्रत्येक बिल के कुल योग पर अगले उच्च रूपये तक शुन्यान्त किया जायेगा।
- (viii) (क) दरों के पैमाने में निर्धारित दरें अधिकतम सीमा स्तर है, इसी प्रकार छूट गृहमूल स्तरों पर है। एसडब्लुपीएल अगर यह चाहे तो निम्न दरों पर चार्ज कर सकती है या/ उच्च छूट की अनुमति दे सकती है।
(ख) यह इस शर्त पर है टर्मिनल प्रचालक इस प्रकार की कमतर दरें और या ऐसी दरों के लागू करने को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करेगा/, और इस प्रकार की निम्नतर या ऐसी कमतर दरों को लागू किए जाने और/बाद में किए जाने वाले परिवर्तनों को शासित करने वाली शर्तें सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करता रहेगा, बशर्ते कि निर्धारित की गई नई दरें, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरों से ज्यादा न हों।
(ग) टर्मिनल प्रचालक दरों के पैमाने में निर्धारित दरों के इस्तेमाल को शासित करने वाली निर्धारित शर्तों को अगर यह चाहे तो तर्कसंगत कर सकता है, अगर यह तर्कसंगति प्रति यूनिट दर में उपभोक्ता को राहत देती है व दरों के पैमाने में निर्धारित यूनिट दरें उपरी सीमा को पार नहीं करती।
- (ix) तार्किक स्तर के ऐसे विलंबों के लिए, जिनके लिए प्रचालक को जिम्मेदार ठहराया जा सके, उपयोक्ता द्वारा प्रभारों का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

2. बर्थ किराया प्रभार

पोतों के मालिकों, स्वामियों/एजेंटों द्वारा बर्थ किराया प्रभार निम्न दरों के अनुसार देय होगा#

क्रम सं.	पोत	दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसका भाग(रु. में)	
		विदेशगामी पोत	तटीय पोत
(i).	पोत	1.00	0.59

नोट:

- (i) बर्थ किराये की अवधि पोत द्वारा, बर्थ का अधिपत्य करने के समय से संगणित की जायेगी।
- (ii) बर्थ किराए में बर्थ पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं जैसे कि बर्थ में आनाए कचरा को हटवाना, बर्थ की सफाई, अग्नि से सुरक्षा व निगरानी आदि शामिल हैं।
- (iii) यदि पोत एक घंटा या उससे अधिक अवधि के लिए लगातार अनुपलब्धता/प्रचालक के उपकरण खराब होने या विद्युत आपूर्ति न होने या टर्मिनल प्रचालक के स्तर का कोई कारण बर्थ में अकार्य पूर्ण स्थिति में रहता है तो किसी प्रकार का कोई बर्थ किराया नहीं लगाया जाएगा।
- (iv) (क) बर्थ किराया, पोत द्वारा जलयान्रा के लिए तैयार होने का संकेत देने के 4 घंटों बाद बन्द हो जायेगा।

- (ख) बर्थ किराये के बंद होने के लिए निर्धारित 4 घंटे की समय सीमा में ज्वार की अनुकूल स्थिति की कमी, खराब मौसम व रात्रि नौचालन की कमी, जहाज के प्रतीक्षा समय में शामिल नहीं होंगे।
- (ग) पोत के स्वामी/एजेन्ट अनुकूल ज्वार एवं मौसम की स्थितियों के अनुसार केवल जलयान की तैयारी के संकेत देंगे।
- (v) झूठे संकेत के लिए बर्थ किराया जुर्माना एक दिन (24 घंटे) के बर्थ किराया भाड़ा के बराबर होगा।

"इंजिन तैयार नहीं होने या कार्गो संचालन कार्य पूर्ण नहीं होने या पोत के अन्य किसी कारणवश पोत बर्थ से हटने के लिए तैयार न होने की स्थिति में, संचालन के लिए तैयार होने के बारे में पूछने के लिए दिया गया सिग्नल "झूठा या गलत संकेत" होगा। पोत प्रतिकूल ज्वार, रात्रि नौचालन की कमी या विपरीत मौसम स्थितियों के कारण जलयान नहीं कर पाने के दौरान के संकेत, तब की तैयारी के संकेतों शामिल नहीं होते हैं।"

(vi) प्राथमिकता/ निर्गम प्राथमिकता किराया प्रभार:

- (क) बर्थिंग प्राथमिकता :
किसी पोत को प्राथमिक आधार बर्थ प्रदान करने के लिए 24 घंटे का बर्थ किराये के समतुल्य या पर वास्तविक रूकने की कुल अवधि के लिए संगणित बर्थ किराया भाड़ा का 75 प्रतिशत जो कोई भी ज्यादा हो वसूल किया जायेगा।
- (ख) निर्गम प्राथमिकता
पोत को बाहर निकलने में प्राथमिकता के लिए एक दिन (24 घंटे) के किराया भाड़े के बराबर शुल्क या बर्थ पर रूकने की वास्तविक कुल अवधि के किराया भाड़े का 100 प्रतिशत जो भी उच्चतम हो वसूल किया जाएगा।

(3) कार्गो प्रहस्तन प्रभार

क्रम सं.	वस्तु	इकाई	दर रु. में	
			विदेशगामी	तटीय
(क)	कोयला प्रहस्तन प्रभार (तापीय कोयला)	प्रति मीट्रिक टन	175.60	175.60
(ख)	कोयला प्रहस्तन प्रभार (तापीय कोयला से भिन्न कार्गो)	प्रति मीट्रिक टन	175.60	105.36

नोट:

ऊपर निर्धारित प्रहस्तन प्रभार पोत कार्य पूरा हो जाने के बाद 15 दिन की अवधि के लिए स्टेक यार्ड के लिए पोत से कार्गो के उतारे जाने, ले जाने, भंडारण, पोत पर लदान तथा वैगनों पर कार्गो के लदान स्थान तक स्थानांतरण, तथा अन्य सभी विविध सेवाओं के लिए मिश्रित रूप से दिए गए हैं।

(4) भंडारण प्रभार :

स्टेकयार्ड में भंडारित कार्गो, निशुल्क अवधि से अधिक समय के लिए भंडारण करने पर भंडारण प्रभार निम्न अनुसार लिया जाएगा।

क्रम सं.	विवरण	निशुल्क अवधि के पश्चात प्रथम 10 दिन के लिए दर	26वें दिन से आदे शेष कार्गो के लिए
1.	कोयला (सभी प्रकार का)	रु. 16.21 प्रति मी.टन	रु.32.42 प्रति मी टन

नोट:

- (i) 15 दिन की निशुल्क अवधि प्रदान की जाएगी। आयातित कार्गो के लिए निशुल्क अवधि आयातित कार्गो के पत्तन में वास्तविक तौर पर प्राप्त होने से आरंभ होगी। निशुल्क अवधि की गणना के लिए सीमाशुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित अवकाश और टर्मिनल के अकार्य दिवस शामिल नहीं हैं।

- (ii) निर्यात हेतु कार्गों के लिए निशुल्क अवधि, प्रचालक के क्षेत्र में सामान के पहुंच की वास्तविक तिथि से आरंभ होगी।
- (iii) आयातित सामान के लिए निशुल्क अवधि, पोत से सामान के पूरी तरह उतर जाने के बाद से मानी जाएगी।

6. अनुसूची 2 से 4 के लिए सामान्य नोट :

- (i). प्रशुल्क सीमा में 1 जनवरी, 2015 और प्रासंगिक वर्ष की प्रथम जनवरी के मध्य थोक मूल्य सूचकांक(डब्ल्यूपीआई) के उतार चढ़ाव के 60% की सीमा तक सूचकांकित वृद्धि की जाएगी। प्रशुल्क सीमा की यह सूचकांकित वृद्धि प्रत्येक वर्ष स्वतः समंजित तथा प्रासंगिक वर्ष की पहली अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक लागू रहेगी।
- (ii). वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की तारीख से उसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, प्रशुल्क सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क तक सीमित किया जाएगा जो अधिकतम होगा। संदर्भ प्रशुल्क, 2013 के संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों के पैरा 2.2 में यथा दिए गए अनुसार सूचकांकन के आधार पर प्रत्येक वर्ष स्वतः ही संशोधित किया जाएगा जो परियोजना की लाइसेंस अवधि के लिए लागू होगा।

तथापि लाइसेंस धारक, आगामी वित्तीय वर्ष से कम से कम 90 दिन पूर्व प्रासंगिक वर्ष के सूचकांकित प्रशुल्क से ऊपर, प्रचालन के दूसरे वर्ष से आगे कार्य निष्पादन मानकों ("कार्यनिष्पादन संबंधी प्रशुल्क") सहित प्रशुल्क प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसा कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क, उस प्रासंगिक उस वित्तीय वर्ष के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (और यह प्रशुल्क सीमा होगी) कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा।
- (iii). प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव के साथ लाइसेंस करार में यथा शामिल पिछले 12 माह अथवा प्रचालन के प्रथम वर्ष में प्रचालन के महीनों की वास्तविक संख्या जैसी भी स्थिति हो, में कार्य निष्पादन मानकों की उपलब्धि दर्शाते हुए परियोजना के रियायत करार के अधीन नियुक्त किए गए स्वतंत्र इंजीनियर से प्राप्त प्रमाण पत्र जमा किया जाएगा।
- (iv). प्रस्ताव के प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर प्राधिकरण, 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देश के पैरा-5 में के अनुसार कार्य निष्पादन मानकों के पूरा किए जाने के बारे में महापत्तन न्यास के विचार मांगेगा।
- (v). लाइसेंस धारक द्वारा, पिछले 12 माह में लाइसेंस करार में शामिल निष्पादन मानकों के पूरा न होने की स्थिति में प्राधिकरण, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क अधिसूचित करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा और लाइसेंस धारक केवल आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लागू सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क के लिए हकदार होगा।
- (vi). महापत्तन न्यास के विचारों पर विचार करने के पश्चात यदि प्राधिकरण संतुष्ट होता है कि रियायत करार में यथा शामिल किए गए कार्य निष्पादन मानक पूरे किए गए हैं तो प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से लागू किए जाने के लिए 15 मार्च तक कार्य निष्पादन संबंधित प्रशुल्क अधिसूचित करेगा।
- (vii). कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क के लिए प्रस्ताव पर विचार करते समय, प्राधिकरण कार्य निष्पादन मानक और लाइसेंस धारक द्वारा इनका अनुपालन देखेगा। प्राधिकरण लाइसेंस धारक द्वारा कार्य निष्पादन मानकों के पूरा किए जाने अथवा अन्यथा के आधार पर कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने पर निर्णय लेगा। सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क और कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क का निर्धारण, 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के साथ उदाहरण के तौर पर संलग्न "परिशिष्ट" के अनुसार होगा।
- (viii). प्रचालन के तीसरे वर्ष से लाइसेंस धारक से प्राप्त कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क प्रस्ताव, स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा यथा प्रमाणित पिछले 12 माह की अवधि में कार्य निष्पादन मानक अर्जित करने पर प्राधिकरण द्वारा स्वतः ही अधिसूचित किया जाएगा। लाइसेंस धारक, तीसरे वर्ष से आगे कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क के लिए 1 मार्च तक स्वतंत्र इंजीनियर से प्राप्त उपलब्धि प्रमाण पत्र के साथ कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क प्रस्ताव पेश करेगा और प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष से प्रभावी कार्य निष्पादन संबंधी प्रशुल्क 20 मार्च तक अधिसूचित करेगा।

अनुलग्नक - II**"पारादीप पत्तन पर बीओटी आधार पर नई कोयला बर्थ के लिए काग्न निष्पादन अनुसूची"****1. बर्थ का समस्त कार्य**

ये मानदंड टर्मिनल पर विभिन्न प्रकार के कार्गो के लिए समग्र कार्य निष्पादन से संबंधित कोयले के प्रहस्तन की स्थिति में टर्मिनल की क्षमता (प्रहस्तन के मशीनी माध्यम से) और पार्सल आकार से ही समग्र निष्पादन का निर्धारण होगा। उच्चतर टर्मिनल क्षमता और पोत(पार्सल) का बड़ा आकार होने से उत्पादन क्षमता में सुद्धि होगी। यह समग्र निष्पादन एक माह में पोत पर प्रहस्तित कुल कार्गो को टर्मिनल पर पोत के व्यतीत हुए समय से विभाजित करके उस माह के दौरान उस टर्मिनल पर पोतीय दिवसों से घंटों से गुणा करते हैं। पोतीय घंटों से पोत दिवसों का निर्धारण करते समय चार घंटों को बर्थ समय की कुल घंटों से घटा दिया जाता है।

सभी कार्गो के निष्पादन के लिए समग्र बर्थ निष्पादन मानक 48000/दिन हैं। कमी की स्थिति में निर्धारित कार्य निष्पादन मानक में अनुमत्त: 70 प्रतिशत

2. स्थानांतरण/भंडारण काल:**(1) बल्क कार्गो:**

कोयला कार्गो और अन्य कार्गो के लिए स्थानांतरण/भंडारण काल, एक माह में उपयुक्त कार्गो पोतों के औसत पार्सल आकार के अर्धभाग को पत्तन से कार्गो के प्रतिदिन औसत निपटान से विभाजन करके निकाला जाएगा।

$$\text{कार्गो का औसत निपटान प्रतिदिन (क)} = \frac{\text{ओबी + प्राप्त/प्रेषित - सीबी}}{\text{दिनों की संख्या}}$$

पी

ओबी = पिछला शेष, सीबी = अन्तिम शेष

$$\text{औसत पार्सल आकार (ख)} = \frac{\text{पी1 + पी2 + + पीएन}}{\text{एन(पार्सलों की संख्या)}}$$

पी 1, पी 2 पीएन का अभिप्राय एक माह में प्रत्येक पोत का पार्सल का आकार से है

बल्क कार्गो के लिए अंतरण भंडारण काल = 0.5 (बी/ए)

सभी प्रकार के कोयले के लिए अंतरण भंडारण काल, वैगन लदान कार्य शुरू होने तक 15 दिन होगा।

कमी की स्थिति में निर्धारित कार्य निष्पादन मानक में अनुमत्त : -20 प्रतिशत

3. आगम / निर्गम कार्य के लिए टर्न अराऊंड समय

आगम / निर्गम कार्य के लिए टर्न अराऊंड समय एक माह में कार्गो के लदान के लिए कुल समय को लगाए गए रेकों से विभाजित (जैसी भी स्थिति हो) करके कलित किया जाएगा। रेक पर लदान और उत्तरायी की स्थिति में एक बार ही प्रवेश पर) उन रेकों के लिए दो गुणा समय प्रदान किया जाएगा। मानक इस प्रकार होंगे :

सभी कार्गो के लिए मानक (एकल-प्रचालन : 10 घंटे)

सभी कार्गो के लिए मानक (दोहरा-प्रचालन : 18 घंटे)

प्रति रेक 58 बीओएसएन वैगन

कमी की स्थिति में निर्धारित कार्य निष्पादन मानक में अनुमत्त : - 10 प्रतिशत

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION**

Mumbai, the 6th February, 2017

No. TAMP/68/2016-PPT.— In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Paradip Port Trust for development of New Coal Berth for handling of Coal imports at Paradip Port on BOT Basis, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/68/2016-PPT

Paradip Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 2nd day of January, 2017)

This Authority had passed an Order no. TAMP/18/2008-PPT dated 14 July 2008, interalia, fixing upfront tariff for handling Thermal coal and Coal other than Thermal coal at deep draught coal berth at Paradip Port Trust (PPT), in pursuance of the 2008 guidelines for upfront tariff setting for PPP projects at Major Ports. This Order was notified in the Gazette of India on 16 August 2008 vide Gazette no. 133.

1.2. Subsequently, based on the proposal filed by PPT, this Authority had passed an Order no. TAMP/44/2015-PPT dated 4 September 2015 fixing Reference tariff for Mechanization of CQ-1 and 2 Berths at the PPT on BOT basis, by adopting the upfront tariff fixed for the Deep Draught Coal Berth in July 2008, in pursuance of the Reference Tariff Guidelines of 2013 as then proposed by PPT. This Order was notified in the Gazette of India on 29 September 2015 vide Gazette no. 335. On the ground that the handling rates and performance standards in respect of Dolomite and Limestone would be same as that of Coal and that Dolomite and Limestone constitute only about about 10% of the Capacity utilisation, the rate in respect of coal was adopted in respect of Limestone and Dolomite in the said Order dated 4 September 2015.

2.1. In this backdrop, the PPT under cover of its letter No. CE/DC/ACCTS/4/16(Pt.I)/1075 dated 3 November 2016 has filed a proposal for development of New Coal Berth for handling of Coal imports at Paradip Port on BOT Basis, with an optimum capacity of 10 Million Tonnes per annum at an estimated capital cost of ₹. 655.56 crores by adopting the Reference tariff of coal fixed for "Mechanization of CQ-1 & 2 berths on BOT basis at PPT. The PPT in its proposal has also stated that, due to unavoidable reasons, the Concession Agreement signed for "Development of Deep Draft Coal Berth on BOT basis" was required to be terminated and the project has been put to retender after updating the cost estimate.

2.2. The tariff proposed by the PPT is as follows:

(a) Cargo Handling Charges:

(Rate in ₹ Per Metric Tonne)

Sr. no.	Commodity	Foreign	Coastal
a.	Coal handling charges (Thermal Coal)	175.60	175.60
b.	Coal handling charges (for other than Thermal coal)	175.60	105.36

(b) Berth Hire Charges:

Rate per GRT per hour or part thereof (₹.)

Sr. No.	Vessels	Foreign Going Vessel	Coastal Vessel
1.	All Vessels	1.00	0.59

(c). Storage charges:

Sr. No.	Commodity	Rate for first 10 days for the balance cargo remaining after the free period	Rate for 26 th day onwards for the balance cargo
1.	Coal (all types)	₹. 16.21 per MT per day	₹. 32.42 per MT per day

2.3. The PPT had also proposed the Performance Standards.

3.1. The Tariff Order of September 2015 as proposed to be adopted by PPT, as brought out earlier, prescribes Reference tariff in respect of handling of Coal, Limestone and Dolomite, whereas, in the proposed new berth, handling of only thermal coal and coal other than thermal coal is envisaged. Given that an approved upfront tariff for handling of Thermal coal and Coal other than Thermal coal at a deep draught coal berth is available, it was felt appropriate to adopt the said upfront tariff with appropriate indexation to arrive at the Reference tariff for the proposed new coal berth.

3.2. In this context, the PPT was requested to furnish some information/clarification vide our letter dated 22 November 2016. The PPT has responded vide its letter dated 02 December 2016. The information sought by us and the response of PPT thereon are tabulated below:

Sl. No.	Information/ clarification sought by us	Response of PPT
(i).	<p>From the aforesaid proposal of PPT, it is seen that the PPT has proposed to adopt the reference tariff fixed in respect of the 'Mechanization of Berths nos. CQ-1 and 2' vide order no. TAMP/44/2015-PPT dated 04 September 2015, for the proposed new berth for handling Thermal Coal and other than Thermal Coal.</p> <p>In this regard, it is to state that the Order of September 2015 as referred above prescribes Reference tariff in respect of Coal, Limestone and Dolomite, whereas, in the proposed new berth, handling of only thermal coal and other than thermal coal is envisaged.</p> <p>The PPT is aware that an upfront tariff for handling of thermal coal and other than thermal coal at a deep draught coal berth has already been approved for PPT vide Order no. TAMP/18/2008-PPT dated July 2008. That being so, the reason for not proposing to adopt the said upfront tariff with appropriate indexation to arrive at the Reference tariff for the proposed new deep draft coal berth to be clarified.</p>	<p>It may be recalled that the reference tariffs for the project "Mechanization of CQ-1 and 2 Berths at Paradip Port on BOT basis" were determined and notified vide order no. TAMP/44/2015-PPT dated 04 September 2015 based on the earlier approved tariffs for the import coal berth notified by the TAMP vide Order no. TAMP/18/2008-PPT dated July 2008 after indexisation.</p> <p>Further, the indexation factor for FY 2016-17 has been notified by TAMP as "NIL" vide letter no. TAMP/12/2009-Misc dated. 11th April, 2016. Hence, the reference tariff calculated for the present proposal shall be the same in both cases viz. (1) if calculated considering the tariffs notified vide Order no. TAMP/18/2008-PPT dated July 2008 OR (ii) considering the tariffs notified vide order no. TAMP/44/2015-PPT dated 04 September 2015 for the coal component, as it is, considering 'NIL' indexation factor for FY 2016-17.</p>
(ii).	<p>When the Concession Agreement signed for "Development of Deep Draft Berth on BOT basis" has been terminated, the proposal of the PPT to adopt the Reference tariff fixed for a combination of cargo (Thermal coal, Coal other than thermal Coal, Limestone and Dolomite) in the Order dated 4 September 2015 for mechanization of CQ- 1 and 2 berths when a specific tariff is already available for the deep draft coal berth to thermal coal and coal other than thermal coal, needs full justification.</p>	<p>As brought out above, the reference tariffs proposed for the present project will be the same in both scenarios. There will be no mention of lime stone and dolomite in the reference tariff order for the present proposal.</p>
(iii).	<p>Further, from the information of the project details furnished by the PPT now, it is seen that the Capital Cost of the Project is estimated at ₹655.56 Crores. In this connection, by adoption of the upfront tariff prescribed vide Order no. TAMP/18/2008-PPT dated 14 July 2008 or by the adoption of the upfront tariff prescribed vide Order no. TAMP/44/2015-PPT dated 04 September 2015, it is not clear whether PPT has satisfied itself that by adoption of the rates proposed by it, the prospective operator:</p>	<p>The RFP for the proposed project "Development of New Coal Berth for handling of Coal imports at Paradip Port on BOT basis" will be in line with the new Revised Guidelines for determination of Tariff for projects at Major Ports, 2013 ("new Guidelines") which have been effective from July 31, 2013. Hence, the tariff proposal for the proposed project comprising of relevant "Reference Tariff" and "Performance Standards" was submitted for approval.</p> <p>However, in view of the observations of TAMP, the calculation of handling charges considering Revised</p>

	<p>(a). Would be in a position to recover the operating cost and 16% return on the capital investment to the tune of ₹ 655.56 Crores.</p> <p>(b). Would not recover more than the operating cost and 16% return on the capital investment, resulting in windfall gains.</p>	<p>estimated cost and assuming 16 % ROCE is prepared and furnished. As can be seen, this works out to ₹ 184.05/- per tonne vis-a vis the Reference tariff of ₹ 175.60- per tonne proposed for the present proposal.</p> <p>As new guidelines allow Port Trusts to adopt reference tariff fixed for particular commodity under same port trust, PPT proposes to adopt notified reference tariff (for Coal) in respect of the project "Mechanization of CQ-1,2 on BOT basis" notified vide order no. TAMP/44/2015-PPT dated 04 September 2015 and indexise the same as per TAMP norms to current level (with 'NIL' indexisation factor for 2016, this remains the same).</p>
(iv).	<p>In addition, it is also noticed that the storage slabs proposed by PPT in its proposed Scale of Rates are not in line either with the storage slabs prescribed in the Upfront Order of 2008 or with the storage slabs prescribed in the September 2015 order.</p>	<p>The dwell time in the earlier notified tariff circular was 10 days and different slab rates were for payment of storage charges beyond 10 days free period. In the meantime, the terminals that got commissioned in different ports experienced serious operational issues and disputes with such provisions. Ministry of Shipping/ Indian Ports Association in their report have also indicated that the dwell time for import cargo in the current scenario exceeds 30 days. (Copy enclosed)</p> <p>The present proposal for tariffs, while retaining the essential features of cargo handling charges and berth hire charges at the same level as approved earlier, is only modified to the extent of increasing the free period from 10 days to 15 days and changes in the slab rates for storage beyond the free period. The calculation of capacity considering the free storage of 15 days is furnished.</p>

3.3. It was seen that some clarification arising out of response of PPT was required from PPT. Accordingly, we have vide our letter dated 13 December 2016 requested the PPT to furnish some information/ clarification arising out of its response. The PPT has responded vide its letter dated 13 December 2016. The information sought by us and the response of PPT thereon are tabulated below:

Sl. No.	Information/ clarification sought by us	Response of PPT
1	<p>With regard to a specific clarification sought from the port as to whether it has satisfied itself to ensure that the prospective BOT operator would be in a position to recover the admissible operating cost and permissible return on capital employed at 16% by way of adoption of the rates proposed by PPT, the PPT has furnished calculation showing that by considering the capital cost of 504.96 crores and the operating cost and with the 16% Return on capital cost, the handling rate works out to ₹ 184.05 per tonne as against the indexed Reference tariff of ₹175.60 per tonne proposed to be adopted by the PPT for the proposed facility. In this backdrop, the PPT is requested to examine whether by levy of lower rate, the prospective BOT operator would not be put into disadvantageous position.</p>	<p>Paradip Port Trust (PPT) has satisfied itself to keep the cargo handling charges at the same levels as approved for similar cargo handling arrangement for the "Mechanization of CQ-1 and 2 Berths on BOT basis", which would be tendered in due course.</p> <p>The reference tariff earlier notified vide order no. TAMP/44/2015-PPT dated 04 September 2015 for the project "Mechanization of CQ-1 and 2 Berths at Paradip Port on BOT basis" is the base document on which the present proposal is formulated. Accordingly, the Cargo handling charges @ ₹ 175.60 per ton (based on indexation to current levels vis- a-vis 2015) have been proposed.</p>
2	<p>With regard to the position that the storage slabs proposed by PPT are not in line either</p>	<p>The slabs for storage charges have been kept in the following manner as in PPT's view the same is</p>

	<p>with the storage slabs prescribed in the Upfront Order of 2008 or with the storage slabs prescribed in the September 2015 order, the PPT has annexed a copy of the Report of Ministry of Shipping, Indian Ports Association, which indicates that the dwell time for import cargo in the current scenario exceed 30 days. A comparative position of the free days and storage slabs as approved in the July 2008 Order and that proposed by the port is given below.</p> <table><tr><th>SI No.</th><th>Particulars</th><th>As in July 2008 Upfront Tariff Order</th><th>As proposed by PPT for the new Coal Berth</th></tr><tr><td>1.</td><td>Free days</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>2.</td><td>Storage slab</td><td>1st 5 days after free period 6th-10th days after free period 11th day onwards.</td><td>1st 10 days after free period From 26th day onwards.</td></tr></table> <p>In view of the substantial changes in the free period and storage slabs, the PPT is requested to furnish detailed workings to establish that based on the free days and storage slab as proposed by it now, the operator would be in a position to meet the annual revenue requirement of the storage activity, amounting to ₹ 131 lakhs (as relied upon in the July 2008 Order of PPT).</p>	SI No.	Particulars	As in July 2008 Upfront Tariff Order	As proposed by PPT for the new Coal Berth	1.	Free days	10	15	2.	Storage slab	1 st 5 days after free period 6 th -10 th days after free period 11 th day onwards.	1 st 10 days after free period From 26 th day onwards.	<p>reasonable :-</p> <table><tr><th>Sl. No.</th><th>Commodity</th><th>Rate for first 10 days for the balance cargo remaining after the free period of 15 days</th><th>Rate for 26th day onwards</th></tr><tr><td>1.</td><td>Coal (all types)</td><td>₹ 16.21 per MT per day</td><td>₹ 32.42 per MT per day</td></tr></table> <p>It is to reiterate that the dwell time in the earlier notified tariff circular was 10 days and different slab rates were for payment of storage charges beyond 10 days free period. In the meantime, the terminals that got commissioned in different ports experienced serious operational issues and disputes with such provisions. Ministry of Shipping/ Indian Ports Association in their reports have also indicated that the dwell time for import cargo in the current scenario exceeds 30 days. Though it is not in conformity either with 2008 or 2015 notified tariffs, PPT has proposed as above in view of the reports of IPA/ MoS.</p> <p>By changing the norms it is expected that there may not be any revenue loss as it will attract additional cargo due to overall cost of handling.</p>	Sl. No.	Commodity	Rate for first 10 days for the balance cargo remaining after the free period of 15 days	Rate for 26th day onwards	1.	Coal (all types)	₹ 16.21 per MT per day	₹ 32.42 per MT per day
SI No.	Particulars	As in July 2008 Upfront Tariff Order	As proposed by PPT for the new Coal Berth																			
1.	Free days	10	15																			
2.	Storage slab	1 st 5 days after free period 6 th -10 th days after free period 11 th day onwards.	1 st 10 days after free period From 26 th day onwards.																			
Sl. No.	Commodity	Rate for first 10 days for the balance cargo remaining after the free period of 15 days	Rate for 26th day onwards																			
1.	Coal (all types)	₹ 16.21 per MT per day	₹ 32.42 per MT per day																			
3	<p>Based on the average output of the capsized Vessel (50000 tonnes) and panamax vessels (35000 tonnes) and based on the share of capsized vessel and panamax vessel at 80:20, as relied upon in the optimal capacity calculation of deep draught coal berth at PPT, the Gross berth Output works Out to 47000 tonnes per day. As against this, the PPT is seen to have proposed a Gross Berth Output at reduce level of 30000 tonnes per day, in the Performance Standard Schedule. The PPT is requested to propose reasonable and achievable Performance Standards which should not be lower than the output (handling) rate considered in the optimal quay capacity calculation of the PPP project, being relied upon for the purpose of adoption on tariff.</p>	<p>It is a typographical error and the Gross berth Output shall be retained as 48,000 tonnes per day.</p> <p>A copy of the proposed Performance Standard marked as Appendix B is enclosed herewith for your reference.</p>																				

4. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i) This Authority had passed an Order no. TAMP/18/2008-PPT dated 14 July 2008, inter alia, fixing upfront tariff for handling Thermal coal and Coal other than Thermal coal at deep draught coal berth at Paradip Port Trust (PPT), in pursuance of the 2008 guidelines for upfront tariff setting for PPP projects at Major Ports.
- (ii). Subsequently, based on a proposal filed by the PPT in pursuance of Clause 2.2. of the Revised Tariff Guidelines of 2013, which inter alia, stipulate that the Reference Tariff will be the highest tariff fixed for that commodity in the concerned Major Port Trust under the 2008 Tariff Guidelines, this Authority had passed an Order no. TAMP/44/2015-PPT dated

4 September 2015 fixing Reference tariff for Mechanization of CQ-1 and 2 Berths at the PPT on BOT basis, as then proposed by PPT. The Reference tariff so fixed was adoption of the upfront tariff fixed for the Deep Draught Coal Berth in July 2008. In the said Order dated 4 September 2015 on the ground that the handling rates and performance standards in respect of Dolomite and Limestone would be same as that of Coal and that Dolomite and Limestone constitutes only about 10% of the Capacity utilisation, the rate in respect of coal was adopted in respect of Limestone and Dolomite also. Thus, common rates were prescribed for Coal, Limestone and Dolomite.

- (iii). In the case in reference, the PPT envisages to develop New Coal Berth for handling of Thermal coal and Coal other than Thermal coal. For the purpose, the PPT had initially proposed to adopt the tariff of coal fixed for Mechanization of CQ-1 & 2 berths in September 2015. The Order of September 2015 as adopted by PPT as brought out earlier, prescribes Reference tariff in respect of handling of Coal, Limestone and Dolomite, whereas, in the proposed new berth, handling of only thermal coal and coal other than thermal coal is envisaged. Handling of lime stone and dolomite is not envisaged at the proposed facility by PPT. Given that an upfront tariff for handling of Thermal coal and Coal other than Thermal coal for a deep draught coal berth has already been approved for PPT vide Order no. TAMP/18/2008-PPT dated 14 July 2008, this Authority prefers to allow the PPT to adopt the said upfront tariff of July 2008 with appropriate indexation to arrive at the Reference tariff for the proposed new coal berth, rather than partially adopting the rate of Coal prescribed in the September 2015 Order.
- (iv). The Revised Guidelines of 2013 stipulate that while adopting the Reference tariff, the tariff set under the Tariff Guidelines of 2008 shall be escalated to the extent of 60% of WPI per annum, as provided in the said guidelines for the period between 1st January of the year as prescribed in the relevant tariff order of this Authority under 2008 guidelines and 1st January of the subsequent relevant year when the Reference Tariff for the particular project in question is being notified.

The upfront tariff for the deep draught coal berth at the PPT was notified in July 2008. The Upfront Tariff Schedule of PPT specifically states that the base year of Wholesale Price Index (WPI) for indexation in the tariff rates approved in the said Order will be 1 January 2008. Accordingly, the PPT has applied the indexation factor of 35.08% on the tariff caps approved for the deep draught coal berth at PPT vide Order of July 2008. This indexation factor is the indexation factor applicable for reference tariff being fixed in the year 2015 as well as in the year 2016 (since NIL escalation factor has been prescribed for the year 2016) with base WPI as on 1 January 2008.

Thus, the indexed reference tariff for handling Thermal coal and Coal other than Thermal coal at the proposed facility as derived by the PPT based on the indexation factor, is found to be in order.

- (v). The July 2008 Upfront tariff Order had prescribed 10 free days; and, the chargeable slab periods were 1st 5 days after free period, 6th – 10th days after free period and 11th day onwards. In the proposed Reference Tariff Schedule for the new Coal berth, the PPT has proposed a free period of 15 days and the chargeable slab periods as 1st 10 days after free period and from 26th day onwards. In support of the changes proposed in the free days and storage structure, the PPT has reasoned that the terminals that got commissioned in different ports have experienced serious operational issues and disputes with regard to the free days and storage slabs. In this connection, the Ministry of Shipping (MOS)/ Indian Ports Association (IPA) in their reports have indicated that the dwell time for import cargo in the current scenario exceeds 30 days. In view of this position, the PPT has proposed more number of free days and extended chargeable storage slab structure, as compared to the July 2008 Upfront tariff Order, keeping in view the report of IPA/ MOS. It is noteworthy that even with the proposed changes, the port does not expect any revenue loss, as additional cargo will be attracted due to overall cost of handling. Given that the change in the free days and storage slab structure is in view of the report of IPA/ MOS, as reported by the Port and since the port has also confirmed that there will not be any loss of revenue on account of the proposed changes in the storage slab structure, the proposal of the port in this regard, is approved by this Authority.
- (vi). The Reference Tariff Guidelines of 2013 allow the Port Trusts to adopt Reference Tariff fixed for a particular commodity under same port Trust. The PPT is satisfied itself to keep the

cargo handling charge at ₹ 175.60 per tonne as approved for the similar cargo. The judgment of the port in this regard is relied upon.

- (vii). In the proposed reference tariff schedule, the PPT has proposed definitions and the general terms and conditions forming part of the PPT Reference tariff Schedule. In this regard, it is relevant here to mention that the upfront tariff schedule for the deep draught coal berth at PPT approved in July 2008 did not prescribe the definitions, general terms and conditions and the various conditionalities governing the levy of cargo handling charges, storage charges and berth hire charges, which are generally prescribed in the Upfront tariff Schedule of the various major port trusts. However, subsequently while notifying reference tariff for mechanisation of CQ-1 and 2 at PPT which was based on the adoption of upfront tariff for handling coal fixed for PPT in the year 2008, definitions, general terms and conditions and all other conditionalities governing the levy of all charges were prescribed in the Reference Tariff Schedule forming part of the PPT Order no. TAMP/44/2015-PPT dated 4 September 2015. The PPT is also seen to have proposed the same definitions, general terms and conditions and all other conditionalities governing the levy of cargo handling charges, storage charges and berth hire charges forming part of the Reference tariff Schedule of the PPT (Order no. TAMP/44/2015-PPT dated 4 September 2015) in the current Reference tariff Schedule. The definitions and conditionalities as proposed by the PPT in its Scale of Rates are approved.

Further, in the note proposed in Section 3 – Cargo handling charges of the proposed Reference Tariff Schedule, the PPT has incorporated the sentence 'after the time of unloading the cargo from railway wagons'. This sentence does not form part of the Reference tariff Schedule approved either in July 2008 or in September 2015. Further, the sentence is not found to be relevant for an import terminal. But, as per July 2008 Order, the free period would commence after the time of completion of ship. Therefore, this provision is added in the note. In view of this position, the said sentence in the proposed Scale of Rates is deleted.

Also, the conditionalities governing System of classification of vessel for levy of Vessel Related Charges, Criteria for levy of Vessel Related Charges and Cargo Related Charges at Concessional Coastal rate, have been prescribed in the Reference Tariff Schedule in line with the common Order no. TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 and 10 June 2016.

- (viii). The rate and conditions for granting ousting priority berthing/priority berthing will be governed by extant Government guidelines/ orders in the matter and the provisions prescribed in the Scale of Rates of PPT. Accordingly, a note to the effect that for providing 'priority' berthing to any vessel, the Port shall collect fee equivalent to berth hire charges for a single day or 75% of the berth hire charges calculated for the total period of actual stay at the berth, whichever is higher, and for providing 'Ousting priority' to any vessel, the port shall collect a fee equivalent to berth hire charges for a single day or 100% of the berth hire charges calculated for the actual period of stay at the berth, whichever is higher, as prescribed in the existing scale of Rates of PPT is also prescribed in the Reference Tariff Schedule.
- (ix). Clause 2.2 of the revised tariff guidelines of 2013 requires this Authority to prescribe the Reference Tariff along with the Performance Standards. Though the revised guidelines of 2013 do not require the Authority to go into the Performance Standards proposed by the port it may not be unreasonable to assume that the ports would propose reasonable and achievable Performance Standard.

With regard to the performance standards, the PPT has proposed the gross berth output per berth at 48000 tonne per day. The PPT has also stated that the Gross Berth Output shall be calculated as the total cargo handled from the ship during a month divided by the time spent by the ship at the terminal multiplied by number of working days of ships in that month at that terminal. While determining the number of working days from the ship hours, the berth allowance of 4 hours shall be subtracted from the total hours. The Gross Berth Output of 48000 tonnes per day is seen to be based on the average output of the capesize vessels (50000 tonnes) and panamax vessels (35000 tonnes) and based on the share of capesize vessels and panamax vessels at 80:20, as relied upon in the optimal capacity calculation of deep draught coal berth at PPT. The Performance Standards as proposed by PPT with regard to Gross Berth Output is relied upon.

- (x). With regard to prescription of Performance Standard for 'Transit Storage Dwell', the PPT has indicated that the transit dwell time for all types of coal will be 15 days upto commencement of wagon loading operation. The PPT has also prescribed the turnaround time for receipt /

delivery operation for a single operation at 10 hours as well as the double operation at 18 hours. The performance norms as proposed by the PPT are prescribed.

- (xi). In the schedule of performance standards, the PPT has prescribed conditionalities relating to Performance Evaluation and calculation of liquidated damages which state that Performance evaluation shall be made on a quarterly review of the reports furnished by the Concessionaire and/ or the records of the Concessionaire and/or by an enquiry by the Concessioneing Authority. The Concessionaire shall be liable to pay liquidated damages determined at the rate of 1% (one per cent) of the Gross Revenue of the respective quarter for every shortfall of 10% (ten per cent) in the average performance.

The said conditionality is seen to be relevant between the parties entering into a Concession Agreement. The Performance Standard Schedule notified by this Authority need not prescribe conditionalities governing review of reports of the Concessionaire by the Concessioneing Authority and payment of liquidated damages. These conditionalities may form part of the Concession Agreement to be entered by the parties, if PPT so desires, and hence not incorporated in the Performance Standard Schedule notified by this Authority.

5.1. Subject to above, the Reference Tariff Schedule along with conditionalities governing the Reference Tariff has been modified.

5.2. The modified Reference Tariff Schedule is attached as **Annex – I** and the Performance Standards for the new Coal Berth, is attached as **Annex – II**.

5.3. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the modified Reference Tariff Schedule for the new Coal Berth at PPT is approved and notified along with the Performance Standards.

5.4. As per clause 2.5 of the Revised Tariff Guidelines 2013, the Reference Tariff and Performance Standards notified by this Authority shall be mentioned in the bid document and subsequently in the Concession Agreement in respect of PPP Projects. Accordingly, the PPT is advised to incorporate the Reference Tariff and Performance Standards, in the bid document and subsequently in the Concession Agreement in respect of PPP Projects.

6.1. From the date of Commercial Operation (CoD) till 31st March of the same financial year, the tariff would be limited to the indexed Reference Tariff relevant to that year, which would be the ceiling. The aforesaid Reference Tariff shall be automatically revised every year based on an indexation as provided in para 2.2 of the tariff guidelines of 2013 which will be applicable for the entire concession period.

However, the PPP operator would be free to propose a tariff along with Performance Standards (the "Performance Linked Tariff") from the second year of operation onwards, over and above the indexed Reference Tariff for the relevant financial year, at least 90 days before the 1st April of the ensuing financial year. Such Performance Linked Tariff shall not be higher than 15% over and above the indexed Reference Tariff for that relevant financial year (and this will be the Tariff Cap). The Performance Linked Tariff would come into force from the first day of the following financial year and would be applicable for the entire financial year.

6.2. The proposal shall be submitted to TAMP along with a certificate from the independent engineer appointed under the Concession Agreement of the Project indicating the achievement of Performance Standards in the previous 12 months as incorporated in the Concession Agreement or for the actual number of months of operation in the first year of operation as the case may be.

6.3. On receipt of the proposal, TAMP will seek the views of the PPT on the achievement of Performance Standards as outlined in para 5 of the tariff guidelines of 2013, within 7 days of receipt.

6.4. In the event of Operator not achieving the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement in previous 12 months, TAMP will not consider the proposal for notifying the Performance Linked Tariff for the ensuing financial year and the Operator shall be entitled to only the indexed Reference Tariff applicable for the ensuing financial year.

6.5. After considering the views of the PPT, if TAMP is satisfied that the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement have been achieved, it shall notify the performance linked tariff by 15th of March to be effective from 1st of April of the ensuing financial year.

6.6. While considering the proposal for Performance Linked Tariff, TAMP will look into the Performance Standards and its adherence by the Operator. TAMP will decide on the acceptance or rejection of the Performance Linked Tariff proposal based on the achievement or otherwise of the Performance Standards by

the operator. Determination of indexed Reference Tariff and Performance Linked Tariff will follow the illustration shown in the Appendix attached to the tariff guidelines of 2013.

6.7. From the third year of operation, the Performance Linked Tariff proposal from the PPP operator shall be automatically notified by TAMP subject to the achievement of Performance Standards in the previous 12 months period as certified by the Independent Engineer. The PPP operator, for the Performance Linked Tariff from the third year onwards, will submit the Performance Linked Tariff proposal along with the achievement certificate from the independent engineer by 1st March and TAMP shall notify by 20th March, the Performance Linked Tariff to be effective from the ensuing financial year.

6.8. In the event any user has any grievance regarding non-achievement by the PPP operator of the Performance Standards as notified by the TAMP, he may prefer a representation to TAMP which, thereafter, shall conduct an inquiry into the representation and give its finding PPT. The PPT will be bound to take necessary action on the findings as per the provisions of the respective Concession Agreement.

6.9. Within 15 (fifteen) days of the signing of the Concession Agreement, the concerned operator will forward the Concession Agreement to TAMP which will host it on its website.

6.10. The PPP operator shall furnish to TAMP quarterly reports on cargo traffic, ship berth day output, average turnaround time of ships, average pre-berthing waiting time as well as the tariff realized for each berth. The quarterly reports shall be submitted by the PPP operator within a month following the end of each quarter. Any other information which may be required by TAMP shall also be furnished to them from time to time.

6.11. TAMP shall publish on its website all such information received from PPP operator. However, TAMP shall consider a request from any PPP operator about not publishing certain data/ information furnished which may be commercially sensitive. Such requests should be accompanied by detailed justification regarding the commercial sensitiveness of the data/information in question and the likely adverse impact on their revenue/ operation of upon publication. TAMP's decision in this regard would be final.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.- III/4/Exty./427/16/(143)]

Annex – I

REFERENCE TARIFF SCHEDULE

“Development of new Coal Berth for handling of Coal Imports at Paradip Port Trust on BOT basis.

1.1. DEFINITIONS

In this Scale of Rates unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

- (i). **“Coastal vessel”** shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal licence issued by the Competent Authority/Director General of Shipping.
- (ii). **“Foreign-going vessel”** shall mean any vessel other than Coastal vessel.
- (iii). **“Day”** shall mean the period starting from 6.00 A.M. of a day and ending at 6.00 A.M. on the next day.

1.2. GENERAL TERMS & CONDITIONS

- (i). The status of the vessel, as borne out by its certification by the Customs or the Director General of Shipping, shall be the deciding factor for its classification as ‘coastal’ or ‘foreign-going’ for the purpose of levying vessel related charges; and, the nature of cargo or its origin will not be of any relevance for this purpose.
- (ii) (a). System of classification of vessel for levy of Vessel Related Charges (VRC)
 - (i). A foreign going vessel of Indian Flag having a General Trading Licence can convert to Coastal run on the basis of a Customs Conversion Order. Such vessel that converts into coastal run based on the Customs Conversion Order at her first port of call in Indian Port, no further custom conversion is required, so long as it moves on the Indian Coast.
 - (ii). A foreign going vessel of foreign flag can convert to coastal run on the basis of a Licence for Specified period or voyage issued by the Director General of Shipping and a custom conversion order.

- (b). Criteria for levy of Vessel Related Charges (VRC) at Concessional Coastal rate and foreign rate.
- (i). In cases of such conversion, coastal rates shall be chargeable by the load port from the time the vessel starts loading coastal goods.
 - (ii). In cases of such conversion coastal rates shall be chargeable till the vessel completes discharging operations at the last call of Indian Port; immediately thereafter, foreign-going rates shall be chargeable by the discharge ports.
 - (iii). For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal Licence from the Director General of Shipping, no other document will be required to be entitled to coastal rates.
- (iii) Criteria for levy of Cargo Related Charges (CRC) at Concessional Coastal Rate
- (a). Foreign going Indian vessel having General Trading License issued for 'worldwide and coastal' operation should be accorded applicable coastal rates with respect to Handling Charges (HC) i.e. ship to shore transfer and transfer from/ to quay to/ from storage yard including wharfage in the following scenario:
 - (i). Converted to coastal run and carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian port.
 - (ii). Not converted* to costal run but carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.

*The Central Board of Excise and Customs Circular no.15/2002-Cus. dated 25 February 2002 allows carriage of coastal cargo from one Indian Port to another port in India, in Indian flag foreign going vessels without any custom conversion.
 - (b). In case of a Foreign flag vessel converted to coastal run on the basis of a License for Specified period or voyage issued by the Director General of Shipping, and a Custom Conversion Order, the coastal cargo/ container loaded from any Indian Port and destined for any other Indian Port should be levied at the rate applicable for coastal cargo/container.
- (iv). (a) The berth hire charges for all coastal vessels should not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels.
- (b) The cargo related charges for all coastal cargo other than thermal coal should not exceed 60% of the normal cargo related charges.
- (c) In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship shore transfer and transfer from/to quay to/from storage yard including wharfage.
- (d) Cargo from a foreign port which reaches an Indian Port "A" for subsequent transshipment to Indian Port "B" will be levied the concession charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo from/to Indian Ports carried by vessels permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession.
- (v). Interest on delayed payments / refunds.
- (a) The user shall pay penal interest on delayed payments under this Scale of Rates. Likewise, the terminal operator shall pay penal interest on delayed refunds.
 - (b) The rate of penal interest will be 2% above the prime lending rate of the State Bank of India.
 - (c) The delay on refunds will be counted only 20 days from the day of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.
 - (d) The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the terminal operator. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services where payment of charges in advance is prescribed as a condition in the scale of rates.

- (vi). In calculating the gross weight or measurement by volume or capacity of any individual item, fractions upto and inclusive 0.5 shall be taken as 0.5 unit and fractions of above 0.5 shall be treated as one unit, except where otherwise specified.
- (vii). All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of the bill.
- (viii). (a). The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels: likewise, rebates and discounts are floor levels. The terminal operator may, if they so desire, charge lower rates and / or allow higher rebates and discounts.
- (b). The terminal operator may also, if they so desire, rationalise the prescribed conditionalities governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates if such rationalisation gives relief to the user in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling levels.
- (c). The terminal operator should notify the public such lower rates and/ or rationalisation of the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.
- (ix). Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to terminal operator.

2. BERTH HIRE CHARGES:

The Berth Hire charges payable by masters/owners/agents for the vessel shall be as per rates below:

Sl. No.	Vessels	Rate per GRT per hour or part thereof (₹)	
		Foreign Going Vessel	Coastal Vessel
1.	All Vessels	1.00	0.59

Notes:

- (i). The period of berth hire shall be calculated from the time vessel occupied the berth till she vacates the berth.
- (ii). Berth hire includes charges for services rendered at the berth, such as occupation of berth, rubbish removal, cleaning of berths, fire watch etc.
- (iii). No berth hire shall be levied for the period when the vessel idles at its berth for continuous one hour or more due to non-availability/break down of terminal operator's equipment or power failure or any reasons attributable to the terminal operator.
- (iv). (a). Berth hire shall stop four hours after the time of the vessel signaling its readiness to sail.
- (b). The time limit of 4 hours prescribed for the cessation of the berth hire shall exclude the ship's waiting time for want of favorable tide conditions, inclement weather and due to lack of night navigation.
- (c). The Master/ agent of the vessel shall signal readiness to sail only in accordance with favorable tidal and weather conditions.
- (v). The Penal berth hire shall be equal to one-day's (24 hours) berth hire charges for a false signal.

"False Signal" would be when the vessel signals readiness and asks for a pilot in anticipation even when she is not ready for un-berthing due to engine not being ready or cargo operation not completed or such other reasons attributable to the vessels. This excludes signaling readiness when a vessel is not able to sail due to unfavorable tide, lack of night navigation or adverse weather conditions."
- (vi). Priority and Ousting Priority charges:-
 - (a) Priority Berthing:
For providing 'priority' berthing to any vessel, the Port shall collect fee equivalent to berth hire charges for a single day or 75% of the berth hire charges calculated for the total period of actual stay at the berth, whichever is higher.
 - (b) Ousting Priority:

For providing 'Ousting priority' to any vessel, the port shall collect a fee equivalent to berth hire charges for a single day or 100% of the berth hire charges calculated for the actual period of stay at the berth, whichever is higher.

3. CARGO HANDLING CHARGES:

The cargo handling charges at the new Coal berth at Paradip Port shall be payable on the manifested cargo directly by the importer of cargo at the rates specified below:

Sl. No.	Commodity	Unit	Rate in Rupees	
			Foreign	Coastal
a.	Coal handling charges (Thermal coal)	Per Metric Tonne	175.60	175.60
b.	Coal handling charges (for other than Thermal coal)	Per Metric Tonne	175.60	105.36

Note:

The above rate is the composite rate for unloading of all the cargo from the ship, conveying to stack yard, storage at the stack yard upto free period of 15 days after the time of completion of ship, reclaiming from stack yard and loading on to the railway wagons and all other miscellaneous services provided.

4. STORAGE CHARGES:

The Storage charges for the cargo stored in the stack yard beyond the free period shall be as below:

Sl. No.	Commodity	Rate for first 10 days for the balance cargo remaining after the free period	Rate for 26 th day onwards for the balance cargo
1.	Coal (all types)	₹ 16.21 per MT per day	₹ 32.42 per MT per day

Notes:

- 15 free days shall be allowed. Free period for import cargo shall commence from the actual date of the receipt of goods in the Port premises. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.
- Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non-working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.
- Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the Terminal operator

5. General Note to Sl no. 2 to 4 above:

- The Reference Tariffs will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2016 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of Reference Tariffs will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.
- From the date of Commercial Operation (CoD) till 31st March of the same financial year, the tariff would be limited to the indexed Reference Tariff relevant to that year, which would be the ceiling. The aforesaid Reference Tariff shall be automatically revised every year based on an indexation as provided in para 2.2 of the tariff guidelines of 2013 which will be applicable for the entire licence period.

However, the Licensee would be free to propose a tariff along with Performance Standard (the "Performance Linked Tariff") from the second year of operation onwards, over and above the indexed Reference Tariff for the relevant financial year, at least 90 days before the 1st April of the ensuing financial year. Such Performance Linked Tariff shall not be higher than 15% over and above the indexed Reference Tariff for that relevant financial year (and this will

- be the Tariff Cap). The Performance Linked Tariff would come into force from the first day of the following financial year and would be applicable for the entire financial year.
- (iii). The proposal shall be submitted to TAMP along with a certificate from the independent engineer appointed under the Concession Agreement of the Project indicating the achievement of Performance Standard in the previous 12 months as incorporated in the Licence Agreement or for the actual number of months of operation in the first year of operation as the case may be.
 - (iv). On receipt of the proposal, TAMP will seek the views of the Major Port Trust on the achievement of Performance Standard as outlined in para 5 of the tariff guidelines of 2013, within 7 days of receipt.
 - (v). In the event of Licensee not achieving the Performance Standard as incorporated in the Licence Agreement in previous 12 months, TAMP will not consider the proposal for notifying the Performance Linked Tariff for the ensuing financial year and the Licensee shall be entitled to only the indexed Reference Tariff applicable for the ensuing financial year.
 - (vi). After considering the views of the Major Port Trust, if TAMP is satisfied that the Performance Standard as incorporated in the Concession Agreement have been achieved, it shall notify the performance linked tariff by 15th of March to be effective from 1st of April of the ensuing financial year.
 - (vii). While considering the proposal for Performance Linked Tariff, TAMP will look into the Performance Standard and its adherence by the Licensee. TAMP will decide on the acceptance or rejection of the Performance Linked Tariff proposal based on the achievement or otherwise of the Performance Standard by the Licensee. Determination of indexed Reference Tariff and Performance Linked Tariff will follow the illustration shown in the Appendix attached to the tariff guidelines of 2013.
 - (viii). From the third year of operation, the Performance Linked Tariff proposal from the Licensee shall be automatically notified by TAMP subject to the achievement of Performance Standard in the previous 12 months period as certified by the Independent Engineer. The Licensee, for the Performance Linked Tariff from the third year onwards, will submit the Performance Linked Tariff proposal along with the achievement certificate from the independent engineer by 1st March and TAMP shall notify by 20th March, the Performance Linked Tariff to be effective from the ensuing financial year.

Annex-II**PERFORMANCE STANDARDS****Schedule of Performance Standards for “New Coal Berth at Paradip Port on BOT Basis”****1. Gross Berth Output**

The parameter deals with the productivity of the terminal (Gross Berth Output) for different types of cargo. In case of coal the capability of the terminal (mechanization, method of handling) and parcel size will determine the Gross Berth Output. Higher terminal capability and greater parcel size will lead to high productivity. The Gross Berth Output shall be calculated as the total cargo handled from the ship during a month divided by the time spent by the ship at the terminal multiplied by number of working days of ships in that month at that terminal. While determining the number of working days from the ship hours, the berth allowance of 4 hours shall be subtracted from the total hours.

The norm for Gross Berth Output for all cargo will be 48,000 tonnes / Day.

Weightage in case of a shortfall in meeting the prescribed performance standard - 70%.

2. Transit Storage Dwell**(i) Bulk Cargo:**

The Transit Storage Dwell Time for coal cargo and other cargo shall be calculated, as half of average parcel size of above cargo vessels in a month divided by average disposal of cargo from the port per day as per the following methodology:

$$\text{Average disposal of Cargo per day (A)} = \frac{\text{OB} + \text{Received} / \text{Dispatched} - \text{CB}}{\text{No. of days}}$$

OB = Opening Balance, CB = Closing Balance.

Average Parcel Sizes (B) = $\frac{P1+P2+ \dots + Pn}{n}$

n (no. of parcels)

P1, P2Pn are parcel size of each vessel in a month.

Transit Storage Time for Bulk Cargo = 0.5 (B/A)

The transit dwell time for all type of coal will be 15 days up to commencement of wagon loading operation.

Weightage in case of a shortfall in meeting the prescribed performance standard - 20%

3. Turn around Time for receipt/ delivery operation:

The Turnaround Time for receipt/delivery operation shall be the sum of time taken for loading of cargo divided by the number of rakes deployed, as the case may be, in a month. Further, in case the rake does both unloading and loading operations on a single entry into the terminal, the time allocated shall be doubled for those rakes.

The Norms will be as follows:

Rake for all cargo (Single Operation): 10 Hours

Rake for all cargo (Double Operation): 18 Hours

58 BOXN wagon per rake.

Weightage in case of a shortfall in meeting the prescribed performance standard - 10%